मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 42 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 15 – 21 अक्टूबर 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

बलराज साहनी: जनवादी कलाकार और अग्रणी कम्युनिस्ट.....5

आरएसएस की हिन्दुत्व सोच से बंधे हैं प्रधानमंत्री.....7

वामपंथी जनवादी दलों की लखनऊ में विशाल रैली

'भाजपा हराओ, इंडिया जिताओ' का आह्वान

लखनऊ 12 अक्टूबर 2023: 11 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में वामपंथी जनवादी शक्तियों की एक विशाल रैली संपन्न हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व, पश्चिम उत्तर दक्षिण में बने 75 जिलों से जनता हजारों की संख्या में एकत्रित हुई।

भारत सरकार ने रेलों में जनरल डिब्बे बहुत कम कर दिए थे, जिसकी वजह से गरीब गुरबा बावजूद भारी परेशानियों के भी हजारों की संख्या में जोश–खरोश के साथ रैली स्थल में एकत्रित हुए। लखनऊ में दूर दराज से आए लोग अपने नेताओं को सुनना चाहते थे। राष्ट्रीय नेताओं को भी और राज्य के नेताओं को भी।

इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) के महासचिव सीताराम येचुरी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक के महासचिव जी देवराजन, लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्री जावेद रजा दिल्ली से चलकर लखनऊ आए। अन्य महत्वपूर्ण नेताओं में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर गिरीश, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) की पोलिट ब्यूरो सदस्य श्रीमती सुभाषिनी अली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) के राज्य सचिव डॉ. हीरालाल यादव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के वरिष्ठ नेता ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उत्तर प्रदेश के महासचिव उदयनाथ नाथ सिंह, लोकतांत्रिक जनता दल के प्रादेशिक अध्यक्ष श्री जुबेर अहमद आदि नेता उपस्थित रहे और उन्होंने आई हुई जनता को संबोधित किया।

चार सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने सभा का संचालन किया जिसमें प्रमुख रूप से इम्तियाज अहमद, पूर्व विधायक भाकपा, डी पी सिंह भाकपा (मा), रमेश सिंह सेंगर भाकपा (माले), डाक्टर विश्वास ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक थे।

पूरा सभा स्थल लाल झंडो और पताकाओं से भरा हुआ था और रह रहकर नारों की गूंज उठती रहती थी। जो आई हुई जनता के संघर्ष के मूड को बयां करती थी।

जनता को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। दलित महिलाओं पर हमले बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले किए जाते हैं। डबल इंजन सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जनता को सोचना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। पर यह सरकार किसके साथ है। यह सरकार अडानी एवं अंबानी के साथ है।

उन्होंने पूछा कि सरकार ने कहा था कि 2 करोड नौजवानों को काम मिलेगा पर क्या वह काम मिला। वह नहीं मिला।

श्री मोदी अभी 2 अक्टूबर को राजघाट गए थे। गांधी जी कहते थे कि

अरविन्द राज स्वरूप

ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, तो मैं तो सिर्फ यह कहूंगा कि देश में तीन चार लोग हैं उनको सम्मति होनी चाहिए। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आरएसएस के श्री मोहन भागवत तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने कहा हमारे देश में सबके लिए एक कानून है परंतु भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार देश की जनता की एकता को तोड़ रहे हैं। दलित एवं आदिवासियों पर हमला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की फिलासफी एकता की नहीं है। समानता की नहीं है। उन्होंने कहा देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है।

देश आजाद हुआ था तो गांधी जी हिंदू मुसलमानों को बचाने के लिए दिल्ली से दूर गए थे परंतु मोदी जी को फुर्सत नहीं है कि वह मणिपुर जा सकें। बीजेपी सरकार संविधान बदलने की बात कर रही है। उसने पब्लिक सेक्टर को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है और मोदी जी यह नहीं बोलते की संविधान को बदलकर वह कौन सा संविधान देंगे देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को। बीजेपी को हराना है और धर्मनिरपेक्षता और संविधान को बचाना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन के अंतर्गत वामपंथी पार्टियों भी हैं। समाजवादी पार्टी से भी उन्होंने अपील की कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से सहयोग होना चाहिए जैसे कि वामपंथी दलों का सहयोग तमिलनाडु में है, बिहार में है, और सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। इसलिए हम यूपी में उत्तर प्रदेश में आए हैं। उत्तर प्रदेश ने आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया और अब जब हम ब्रिटिश सरकार को हरा सकते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को भी हरा सकते हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एनडीए गठबंधन को हराना है। उन्होंने पब्लिक का आवाहन किया कि हमको संविधान की रक्षा करनी है और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करना है। उन्होंने उम्मीद की कि उत्तर प्रदेश की जनता अवश्य चुनौतियों का मुकाबला करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में हराएगी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी डॉ. गिरीश ने कहा कि आज की रैली ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई का बिगुल फूंक दिया है। मजदूर, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों के प्रश्न उठाए जाएंगे। महिलाओं के प्रश्न उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है। प्रतिदिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, विकास का दाम और निशान नहीं है, सिर्फ बुलडोजर चला है, सड़के टूटी पड़ी हुई हैं, सरकारी मशीनरी में भारी भ्रष्टाचार है, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार फेल है, वैसे ही दिल्ली में भी सरकार फेल है। उन्होंने कहा कि आज की रैली ने दिखा दिया है की कुछ लोगों को यह मति भ्रम है की उत्तर प्रदेश में वामपंथी कहां है तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वामपंथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटों में है और 80 लोकसभा की सीटों में है और वह भारतीय जनता पार्टी को हराने में अपनी पूरी ताकत लगाएगा आज जनता की रैली इसीलिए यहां पर एकत्रित हुई है उन्होंने आह्वान किया की 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और ऐसा किया जा सकता है। घोसी ने दिखा दिया है।

राष्ट्रीय नेताओं के बोलने से पूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप ने अपने संबोधन में कहा देश में भी और प्रदेश में भी अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है। जनवाद को कमजोर किया जा रहा है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ घोषणाएं होती रहती हैं परंतु वह समस्त घोषणाएं बिल्कुल झूठी हैं। घर–घर में नौजवान बेकार बैठा हैं। दलितों को मारा जा रहा है। दलितों के ऊपर पेशाब करवाया जाता है और आरोपी स्वतंत्र घूमते हैं। उनको कोई डर नहीं है। सरकार इन प्रश्नों से बचने के लिए सांप्रदायिक नारे देती है उसके मंत्री सांप्रदायिक बातें करते हैं। अल्पसंख्यकों को निशाने पर रखा जाता है। जनता के प्रश्नों से बचने के लिए कभी लव जिहाद आ जाता है, कभी गाय आ

शेष पेज 14 पर....

चाहिये, विचारों की आज़ादी!

संपादकीय

हमारे खुले नीले आसमान में आजकल उदासी की धुंध जमा होती जा रही है। पिछले करीब दस सालों से यह हो रहा है। 2014 से ही इसकी शुरूआत हुई। यह मीडिया है, जिसे सत्ता अपने काबू में करना चाहती है। सारी कोशिशें साधारण प्रलोभन से परे हैं। इसमें न प्रोमोशन है और न संस्पेन्ड होने का दंड। यह तो सीधे अस्तित्व मिटाने की ही बात होती है, एक ही बार में या फिर धीरे–धीरे। कुछ तैय्यार परिभाषाएं हैं, निर्दोष–सी दीखने वाली या फिर वह बौद्धिक पुष्टता देने वाला खाद्य जो भारतीय मीडिया को बांधने के लिये है। उदाहरण स्वरूप ''हिन्दू वही है, जिनकी पितृ भूमि भारत है।'' हिन्दुत्व का यह स्क्रिप्ट तैय्यार करना आसान नहीं था, क्योंकि वास्तविकता अलग है और मज़बूत भी, सत्य को नष्ट करना संभव नहीं है, चाहे कितनी ही परतों में डालकर उसे नष्ट करने की कोशिश की जाय। लेकिन ''निरपेक्ष पत्रकारिता'' के लिये सिद्धांतों को तय करने में ही दस साल लग गए। फिर उसे मीडिया की मुख्यधारा बनाने के लिये भी तो मेहनत करना है। लेकिन करने का काम तो बस एक ही है, और वह है दरार पैदा करना। कहीं भी, किसी एकता की हैसियत को बनने नहीं देना है, आज यह चुनौती हम सबके सामने है। जो मानवीयता का अनिवार्य अधिकार है, वैचारिक स्वतंत्रता, उसे पाने का हर द्वार बंद करने की कोशिश है और मीडिया कोई अपवाद नहीं है।

सत्ता पक्ष चाहता है हर नये क़दम को, चाहे वह जनता के लिये हो या नहीं हो, उसे एक उच्चस्तर की प्रशंसा के पैकेट में हर चौबीस घंटे की खबरों में रखा जाय। लेकिन इस दृष्टि से समझौता पूरा सफल नहीं हो पाया है। इसका विकल्प तो सारी दुनिया के समाचार पोर्टलों और यू–ट्यूब चैनलों में मिलता है, लेकिन वह इतना फीका होता है कि भरोसा करना मुश्किल ही होता है। इसलिये सत्ता आज अपनी दशा से उबरने के लिये किसी विकल्प को चुनने के लिये तैय्यार है। और इसलिये बहुलवादी सांप्रदायिक एजेन्डा अपनी अलगाववादी राजनीति के साथ वित्त पूंजी की सेवा में प्रस्तुत हो गया है। लेकिन मीडिया में उन्हें जगह मिलना आज भी कठिन ही रह गया है। 2009 में शुरु किए गये समाचार पोर्टल, जो आज खबरों में है, उनमें से एक न्यूज़क्लिक, अपने बारे में कहता है, ''यह भारत की विविधता की संस्कृति, इसके विभिन्न जन आंदोलन और संघर्षों का नियमित, सुसंगत लेखाकार है।'' कोई भी यह नहीं कहता कि न्यूज़क्लिक के खिलाफ केस को चलने नहीं दिया जाए, पर यह जरूर कहना है कि हर आरोप प्रामाणिक हों, उनके सबूत हों। डर फैलाने की यह सस्ती हरक़त, सबूत मिलने के पहले ही उन पर यू.ए.पी.ए. लागू करना, मोबाइल, लैपटॉप जैसी जरुरी चीजों को जब्त करना पूरी परिस्थिति को कोई औचित्य नहीं दे पाता। जब उन पर चार्ज लग रहे थे, तो दिल्ली पुलिस का कथन था, ''सैंतीस पुरुष और नौ महिलाओं पर संदेह है और उनसे ही प्रश्न किये गए। यू.ए.पी.ए. को इस बिना सबूत के, बिना कारण बताए लागू करना किसी अच्छे भविष्य का संकेत नहीं है। यह भयानक साया आज बहुतों के इर्दगिर्द है।

पत्रकार, या मीडिया की संस्थाएं आज विश्व भर में इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। सभी चाहते हैं अपनी पत्रकारिता में स्वच्छता, वैचारिक स्वंतत्रता बनी रहे। पर बिना किसी आंच के रहे। पूरे विश्व में आज सवाल उठ रहे हैं, मीडिया की आजादी पर, और किसी भी धमकी के डर के बिना स्वतंत्र लेखन पर।

विशेषकर, यह जरुरी है आज जब पुलिस पत्रकारों के घर पर रेड डाल रही है, उनके ऑफिस तक पहुंच रही है, न्यूज़क्लिक की तरह आज़ाद न्यूज़ आउटलेट पर, देश की राजधानी में पहुंच रही है।

सुबह–सुबह दरवाज़े पर ज़ोरदार दस्तक, दुविधा के साथ दरवाजे का खुलना और आतंक के साथ धमकी का सामना, और इस सबसे अचानक बेबस बने व्यक्ति को, बिना सबूत, बिना कारण, बिना कैफियत उठा लिया जाना आज यह सारा दृश्य हमारे सामने आ चुका है।

भारत सरकार के मीडिया के प्रति रुख के विरोध में विश्व भर के पत्रकार सड़कों पर हैं। न्यूयार्क टाइम्स की रिर्पोटिंग से ही ये सारा हंगामा शुरु भी हुआ है, इसलिये उसके ऑफिस पर भी प्रदर्शन हुए, इसमें पोस्टरों पर मैकार्थिज्म के खिलाफ स्लोगन भी था और साथ ही अन्य पोस्टर न्यूज़क्लिक के ऊपर हुए दमन पर भी थे। वे भारत में मीडिया को जिस तरह समझौते या दमन की राजनीति में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी तीखा विरोध था। चौथे खंभे की भूमिका ख़त्म कर डाली गई है।

सरकार अब इसके सामने कोई भी कैफियत देने के लिये अपने को मज़बूर नहीं समझती है। वस्तुतः मैकार्थिज्म'' का अर्थ ही है अवज्ञा और ध्वंस से जुड़े रहने का, बिना पूरे सबूत के ही, आरोप लगाना इसकी जांच और आरोप जहां दोनों ही एक पक्षीय है, ऐसी दमनकारी नीतियों से विरोधी पक्ष को कुचलना। न्यूज़क्लिक में अभी तक कोई सबूत नहीं पेश हुआ है। यह अब एक आदत–सी हो गई है जनता को कि सरकार किसी भी विफलता को साबित करने के लिये सबूत को महत्व नहीं देती। यह इसलिये है कि आरोप में सच्चाई का शुरु से अभाव दीखता है। वस्तुतः इसी सच्चाई को पेश करने की विफलता से डरकर, उससे बचने के लिये मैकार्थी ने ये दमन के क़ानून बनाए थे, लेकिन वह दिन भीआया जब अमेरिका के सीनेट परमानेन्ट इन्वेस्टिगेशन सबकमिटी के चेयरमैन को, जो मैकार्थी स्वयं था, ध्वंस के ही आरोप में अमेरिकन सीनेट ने सेंसर कर दिया। सबूत की आवश्यकता अनिवार्य है। यह 1954 में दिसंबर की दो तारीख को हुआ और 1957 की उसी तारीख को मैकार्थी की मृत्यु हो गई। सबूत अनिवार्य है आरोप के लिये।

आज दिनोंदिन सबूतों की मांग अदालतों में बढ़ती जा रही है। वे इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि बार–बार केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह बिना सबूत किसी पर दमन की कार्रवाई के लिये आगे बढ़ना वे स्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें इसका जवाब चाहिये। शायद वह दिन दूर नहीं जब इस तरह क़ानून को तोड़–मरोड़कर लागू करते हुए केंद्र का आगे बढ़ते जाना कोर्ट को बिल्कुल ही मंजूर न हो।

क़ानून का इसी तरह उपयोग करते हुए जब दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक के प्रतिष्ठाता प्रवीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन के निर्देशक अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने में कोई प्रामाणिक कारण पेश करने से परहेज किया, तो इसपर दोनों ही गिरफ्तार व्यक्तियों को मांगने पर भी आरोप और सबूत दिखाए नहीं गये। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि इन दोनों को ही इसका क़ानूनी अधिकार है कि उन्हें जानने के लिये आरोप और सबूत दिखाए जायं। इसकी हाईकोर्ट ने भी पुष्टि की।

पिछले दिनों लगता है केंद्र की जांच एजेंसियां विभिन्न मामलों में आरोपों के ऊपर सफाई देने से बच भी रही है, शायद इसका एक बड़ा कारण विरोध का संगठित होना, ''इंडिया'' ग्रुप का मज़बूत होना और चुनाव का नज़दीक होना है। यह विरोध मात्र मीडिया तक ही सीमित नहीं है, यह उन सबकी आवाज़ है, जिनके पास न्याय और सत्य है।

पत्रकारिता पर हमले के खिलाफ वाम दलों का विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर 2023: संसद मार्ग, जंतर मंतर पर दिल्ली के सभी वामदलों की ओर से एक धरने का आयोजन किया गया, जिसका संचालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिल्ली राज्य के कार्यवाहक सचिव एवं राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य शंकर लाल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा), दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव के एम तिवारी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के दिल्ली के सचिव रवि राय, अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लॉक, दिल्ली के सचिव धर्मेंद्र वर्मा, आरएसपी आर एस डागर, दिल्ली के सीजीपीआई के बिरजू नायक के किया।

सर्वप्रथम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव एवं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने धरने पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुये न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ तथा अमित चक्रवर्ती की गैर कानूनी। गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हुये कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का प्रयोग करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया के ऊपर हमला किया है तथा प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से स्वतंत्र, निर्भीक व सत्ता से सरोकारी सवाल करने वाले पत्रकारों से पूछताछ के बहाने प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपना फासिस्टी अजेंडा पूरा कर रही है, जनता इसका जवाब मोदी सरकार को आने वाले पाँच राज्यों के चुनाव तथा 2024 के लोकसभा के चुनाव में सत्ता से बेदखल करके देगी।

धरने को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) की पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, एआईएफबी के महासचिव जी देवराजन, आरएसपी के राष्ट्रीय सचिव आर एस डागर, सीजीपीआई के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश राव ने संबोधित किया।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

भाजपा संसद सदस्य द्वारा लोकसभा में अत्यंत आपत्तिजनक नफरत भरे बोल

सर्वोच्च न्यायालय नफरती बयानों के संबंध में बार–बार आदेश दे चुका है कि इन्हें रोका जाए और जो लोग नफरती बयान देते हैं उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने 18 सितंबर 2023 को संसद का विशेष सत्र बुलाया था जिसकी पहली बैठक 18 सितंबर को संसद के पुराने भवन में हुई और 19 तारीख से संसद के नवनिर्मित भवन में अगली बैठकें हुई।

सरकार ने संसद के नए भवन में प्रवेश करते हुए कहा था कि उसमें लोकतंत्र की मर्यादाएं और प्रगाढ़ होंगी। परंतु संसद के इस विशेष सत्र में और नवनिर्मित संसद भवन में भाजपा संसद सदस्य रमेश बिधूड़ी ने संसद में अपने ही साथी एक अन्य संसद सदस्य–दानिश अली–के खिलाफ ऐसे अपमानजनक और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जैसा आज से पहले संसद में कभी नहीं हुआ। बिधूड़ी ने संसद में जिस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए, उन्हें यहां लिखना भी शोभनीय नहीं लगता। भाजपा सांसद के नफरत भरे बोलों ने न केवल भारत की संसद को बल्कि भारत के लोकतंत्र को भी शर्मसार कर दिया है।

अवश्य ही लोकसभा स्पीकर ने उनके शब्दों को संसद के रिकॉर्ड से निकाल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगली बार से ऐसा आचरण सामने आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परंतु क्या इतना ही काफी है?

विपक्षी दलों ने सही ही कहा है कि जब दूसरे दलों के नेताओं से सदन में मामूली–सी चूक होती है तो उन्हें संसद से निलम्बित कर दिया जाता है और बिधूड़ी ने एक साथी संसद सदस्य को सदन के पटल पर गालियां दी, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? उन्हें चेतावनी देकर क्यों छोड़ दिया गया?

यह पहली बार नहीं है कि जब किसी भाजपा के नेता ने नफरत भरा भाषण दिया हो।

नफरत भरे भाषणों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के अन्य तमाम नेताओं में कौन ऐसा है जो नफरत भरे भाषण न देता हो? आम सभाओं में भाजपा के नेता और मंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण देते और अल्पसंख्यक विरोधी नारे लगाते अकसर सुने जाते हैं। असल में तो भाजपा में जो जितने अधिक नफरत भरे भाषण देता है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जितना अधिक बोलता है, पार्टी में उसका कद उतना ही बढ़ जाता है। स्वयं नरेन्द्र मोदी का कद भी ऐसे ही बढ़ा था।

दुनिया भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति भाजपा सरकार और पार्टी के रवैये का नोटिस ले रही है। समय–समय पर विभिन्न संगठन इस बारे में रिपोर्टे देते रहे हैं। इस संबंध में द टेलीग्राफ (कोलकाता, 27 सितंबर 2023) में छपी एक रिपोर्ट में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बढ़ती असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की गयी है। एक अमेरिका आधारित रिसर्च प्रोजेक्ट, ''हिन्दुत्व वाच'' एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट, ''भारत में मुस्लिम विरोधी नफरती भाषण की घटनाएं'' में वर्ष 2023 के पहले छह महीनों में ''मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए नफरती भाषण .....की 255 डॉक्युमेंटिड घटनाओं .....जिनमें से भारी संख्या में नफरती भाषणों की घटनाएं, 205 घटनाएं (80 %) भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में हुई'' का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है: ''कुल मिलाकर, नफरती भाषणों की सभाओं में से 42% सभाएं 17 राज्यों में हुई जिनमें से दो केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं। इनका आयोजन आरएसएस से संबंधित समूहों ने किया.....इस तरह की 33% सभाओं में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का खुलेआम आह्वान किया गया जो चिंताजनक है।''

हिन्दुत्व वाच ने कहा: ''महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इस तरह की सबसे अधिक सभाएं हुई जिनमें नफरत भरे भाषण दिए गए।''

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब विपक्षी पार्टियों ने बसपा संसद सदस्य दानिश अली के खिलाफ भाजपा संसद सदस्य रमेश बिधूड़ी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में बिधूड़ी को निलंबित करने की मांग की है। स्पीकर ने बिधूड़ी को चेतावनी दी है, और उनकी पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिधूड़ी के दो पार्टी साथियों ने बाद में दावा किया कि वह अली द्वारा उकसाये गए थे।

पिछले साल भाजपा ने अपने उन दो प्रवक्ताओं को हटा दिया था जिनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों का नतीजा दंगों और अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के रूप में निकला था।

इस महीने एक भारतीय एनजीओ, यूनाइटिड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) ने कहा कि इस साल के पहले 8 महीनों में ईसाईयों के खिलाफ 525 हिंसक हमले हुए हैं। यूसीएफ ने दर्ज किया है कि 2014 के बाद के हमलों में लगातार वृद्धि हुई है; 2014 में इस तरह की 147 घटनाएं हुई थी। यूसीएफ का डाटा 23 राज्यों का है जिनमें मणिपुर शामिल है जहां मुख्यतः मैतई और कुकी–जो समुदायों के बीच चल रहे टकरावों में 14 सितंबर तक 254 चर्चो और 132 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया।

यूसीएफ ने एक बयान में कहा: ''उत्तर प्रदेश में इस तरह की सबसे अधिक, 131 घटनाएं हुई। इसके बाद दूसरे नम्बर पर छत्तीसगढ़ रहा जहां 118 घटनाएं हुई और हरियाणा में 39 घटनाएं हुई..... ईसाईयों पर हमले भीड़ द्वारा हिंसा तक सीमित नहीं है। 520 ईसाई हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और बिना किसी साबितशुदा साक्ष्य के उन पर जबरन धर्मान्तरण का आरोप लगाया गया''।

मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के कमीशन (यूएससीआईआरएफ) ने लगातार चौथे साल अपनी सरकार से कहा है कि भारत को एक ''विशेष चिंता वाला देश'' घोषित किया जाएं।

अमेरिका के समाचार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है ''राइजिंग इंडिया, टॉक्सिक टेक: इनसाइड द विशाल डिजिटल कैंपेन हिंदू नेशनलिस्ट्स टू इन्फ्लुएंस इंडिया''। लेख में भाजपा सदस्यों और समर्थकों का हवाला देते हुए कहा गया है। रिपोर्ट कहती है: ''इस गहन साक्षात्कारों में, भाजपा और पार्टी के सहयोगियों ने बताया कि वे भारत के बहुसंख्यकों के डर को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से फर्जी पोस्ट बनाते हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने व्हाट्सएप समूहों के विशाल नेटवर्क पर इस सामग्री को प्रचारित करने के लिए 150,000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं का एक विशाल तंत्र इकट्ठा किया था।''

रिपोर्ट में कहा गया है: ''लेकिन पार्टी के आधिकारिक ऑनलाइन प्रयासों से परे, भाजपा कर्मचारियों, अभियान सलाहकारों और पार्टी समर्थकों के अनुसार, एक शैडो समानांतर अभियान भी था। दुर्लभ और व्यापक साक्षात्कारों में, उन्होंने खुलासा किया कि पार्टी चुपचाप सामग्री निर्माताओं के साथ सहयोग करती है जो चलाते हैं जिन्हें बड़े–पार्टी या ''ट्रोल'' पेज के रूप में जाना जाता है, और जो व्हाट्सएप पर वायरल होने और पार्टी के आधार को आग लगाने के लिए डिजाइन किए गए भड़काऊ पोस्ट बनाने में माहिर हैं।''

''अकसर उन्होंने एक ऐसे भारत की भयानक और झूठी तस्वीर पेश की जहां धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित 14 प्रतिशत मुस्लिम अल्पसंख्यक हिन्दू बहुसंख्यक लोगों से दुर्व्यवहार और हत्याएं करते हैं और जहां उन्हें भाजपा को वोट देकर ही न्याय और सुरक्षा मिल सकती है।''

हड़ताली मजदूरों के समर्थन में पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति

अमेरिका में ऑटो मजदूर (कार, बस, मोटरसाइकल आदि के कारखानों में काम करने वाले मजदूर) हड़ताल पर हैं। वे अपने वेतन में 40 % की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। 26 सितंबर को एक अप्रत्याशित घटना हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति मिशिगन शहर में पिकेटिंग करते हुए हड़ताली मजदूरों के बीच जा पहुंचे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और कहा कि मैं आपका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा: ''आप जो कमाते हैं, आपको मिलना चाहिए। आप लोग बहुत मुश्किलें झेलते हैं और आपको बहुत कम वेतन मिलता है।''

एक पत्रकार ने बाइडेन से पूछा कि क्या आप मजदूरों की इस मांग का समर्थन करते हैं कि उनके वेतन में 40 % की बढ़ोतरी की जाए। यूनियन कार्यकर्ताओं के बीच खड़े बाइडेन ने कहा –हां। बाद में व्हाइट हाउस ने एक ट्रान्सस्क्रिप्ट जारी किया जिसमें राष्ट्रपति कहते हुए नजर आते है: ''हां, मैं समझता हूं कि मजदूर इसके लिए सौदेबाजी करने में कामयाब हो जाएंगे।''

यह निश्चित तौर से एक अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक घटना थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति हड़ताली मजदूरों के बीच जाकर उन्हें अपना समर्थन दें। अमेरिका क्या, दुनिया में ऐसा अन्य उदाहरण मुश्किल से ही मिलेगा जहां कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हड़ताली मजदूरों के बीच पहुंचकर इस तरह का समर्थन व्यक्त करें। जहां तक भारत का मामला है यहां तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी मजदूरों को इस तरह समर्थान देने के लिए हड़ताली मजदूरों के बीच पहुंचे। हड़ताली मजदूरों को समर्थन देना तो दूर रहा, मोदी सरकार तो एलानिया कह रही है कि मजदूरों को हड़ताल नहीं करने देंगे। श्रम कानूनों में भी इस तरह के बदलाव कर दिए गए हैं कि न केवल हड़ताली मजदूरों को कुचला जाएगा बल्कि उनका समर्थन करने वालों को भी जेल की सींखचों में भेज दिया जाएगा।

अमेरिका में तीन बड़ी ऑटो कंपनियों–जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिस्लर निर्माता स्टैलान्टिस –में यूनाइटिड ऑटो वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में हड़ताल चल रही है। हड़ताल के 11वें दिन यूनियन के अध्यक्ष शॉन फिन ने राष्ट्रपति को हड़तालियों के बीच आने का निमंत्रण दिया था। उसके निमंत्रण पर राष्ट्रपति वहां पहुंचे और स्वयं को सुस्पष्ट तरीके से मजदूरों के समर्थन में बताया। अब तक व्हाइट हाउस इस हड़ताल के बारे में तटस्थ भूमिका में था।

न्यायपालिका के साथ टकराव के मूड में मोदी सरकार

जब से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम खारिज किया है, ऐसे समाचार आते रहे हैं जिनसे संकेत मिलता है कि मोदी सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव की दिशा में काम कर रही है। पिछले दिनों केंद्र के मंत्री राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलते रहे हैं। यहां तक कि अपने पद की गरिमा का परित्याग कर राज्य सभा के स्पीकर, जगदीप धनखड़ जो भारत के उप–राष्ट्रपति भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं।

सरकार के इसी रवैये का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए जिन लोगों के नाम भेजती है, सरकार उन्हें स्वीकार करने में लगातार देरी करती रही हैं। इसका परिणाम यह है कि सभी उच्च न्यायालयों में जजों के कुल 1,108 पदों में से 337 पद खाली पड़े हैं।

सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में ''देरी'' पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोलेजियम की 70 सिफारिशें अब भी सरकार के पास अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट बंगलुरू की एडवोकेट्स ऐसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने 2021 के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित समयसीमा का कथित तौर पर पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के ख्लिाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने अटार्नी जनरल वेंकटरमणी से कहा, ''आज मैं चुप हूं क्योंकि अटार्नी जनरल ने बहुत कम समय मांगा है, अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा।'' पीठ ने कहा, ''पिछले सप्ताह तक 80 सिफारिशें लंबित थी, जब 10 नामों को मंजूरी दी गई। अब, यह आंकड़ा 70 है जिनमें से 26 सिफारिशें जजों के स्थानांतरण की है, सात सिफारिशें दोहराई गई हैं, नौ कोलेजियम को वापस किए बिना लंबित हैं और एक मामला संवेदनशील उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है।''

अटार्नी जनरल ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था, पीठ ने उन्हें दो हफ्ते का समय दे दिया और केंद्र की दलील के साथ कोर्ट में आने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कहा यह सभी सिफारिशें पिछले साल नवंबर से सरकार के पास लंबित पड़ी हैं।

पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की जिला अदालतों में कुल 5,800 पद खाली थे।

किसानों ने मनाया काला दिवस, मोदी का पुतला फूंका

बेगूसराय 3 अक्टूबर 2023: विश्व के अजूबे और अनोखे दिल्ली किसान आंदोलन को कुचलने की साजिश के तहत विगत 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इशारे पर किसानों की हुई जघन्य हत्या को देश कभी नहीं भूलेगा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 3 अक्टूबर 2023 को देशभर में काला दिवस मनाने का आह्वान तथा जिला प्रशासन के समक्ष धरना, प्रदर्शन, प्रतिरोध मार्च तथा पुतला दहन के माध्यम से अपनी मांगों का स्मार–पत्र जिला समाहर्ता के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजने के लिए आज बेगूसराय जिला समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर किसानों एवं मजदूरों का यह विशाल धरना दिया गया।

इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि विगत 75 वर्षों में हम–आप ने तथा हमारे–आपके पुरखों ने अपना खून जलाकर कठोर मेहनत के बल पर देश में जो दौलत पैदा की उससे देश मे निर्मित सारे सरकारी प्रतिष्ठानों और सम्पत्तियों को अपने दो गुजराती मित्रों के बीच लूटाने में मोदी सरकार मशगूल है। देश की आजादी की लड़ाई में अकूत कुर्बानी के बल पर अर्जित हमारा यह लोकतंत्र, हमारा यह संविधान, राष्ट्रीय एकता–अखंडता, आपसी भाईचारा एवं साझी संस्कृति और साझी विरासत आज खतरे में है। आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, माटी के भाव बेच रहे देश की संपत्ति और गिरती अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दिन–रात देश में नफरत की खेती में मोदी जी ओवर टाइम लगे हुए है। किसानों को लुभाने के लिए 2016 में मोदी जी ने वायदा किया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। मगर महंगे डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक एवं कृषि यंत्रों ने किसानो की आय दोगुनी के बदले आधी से भी कम कर दी है। दिल्ली किसान आंदोलन को स्थगित करने हेतु, देश के किसान संगठनों से मोदी जी ने जो लिखित वायदा किया था। उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। देश का किसान अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आज पुनः देश में दौलत पैदा करने वाला किसान और मजदूर संगठनों ने नारा दिया है लडेंगे–जीतेंगे। एटक की राष्ट्रीय सचिव उषा सहनी ने कहा कि कौन बनाता है हिंदुस्तान, देश का मजदूर किसान।

किसान सभा के कार्यकारी जिला सचिव दिनेश सिंह ने कहा हमारी मुख्य मांग है, लखीमपुर खीरी के किसानों के हत्यारे मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर जेल मे बंद करो। मुकदमे में फंसाए गए निर्दोष किसानों को रिहा करो। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा, उनके परिवार को मुआवजा दो और सिंघु बॉर्डर पर उनका स्मारक का निर्माण अविलंब किया जाए। सभी फसलों के लिए सी–2 का डेढ गुना एमएसपी की कानूनी गारंटी। एटक के राज्य सचिव ललन कुमार ने आंदोलन में किसानों एवं ट्रेड यूनियनों के लोगों पर हुए सभी मुकदमों को वापस लो। श्रम संहिताओं को रद्द करो और न्यूनतम वेतनमान प्रतिमाह 26000 रुपया निर्धारित करो। किसानों, असंगठित मजदूरों एवं खेतिहर मजदूरों को साठ साल की उम्र से 10000 रू. मासिक पेंशन दो। मनरेगा को कृषि से जोड़कर 600 रू. दैनिक मजदूरी के साथ साल में 200 दिन काम की गारंटी हो। किसान सभा के जिला सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि किसानो की कर्ज मुक्ति, सार्वजनिक उद्योगों और सेवाओं के निजीकरण पर रोक, सुखा से तबाह बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करो आदि मांगों को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सभा को किसान नेता अनिल अंजान ने संबोधित करते हुए किसानों को ललकारते हुए संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया। सभा को नवीन कुमार, अशोक राय, नागेंद्र राय,राम प्रमोद सिंह, प्रमोद महतो, मो मुजाहिद हुसैन एवं मनोज कुमार आदि ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता एटक महासचिव प्रहलाद सिंह तथा किसान नेता राम नरेश महतो ने की। सभा के बाद प्रतिरोध मार्च निकाला गया जो नगर–निगम चौक, नवाब चौक होकर कैंटीन चौक पर आकर किसानों का सबसे बडे दुश्मन प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को मुखाग्नि दी गई।

एआईएसएफ का मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन

मथुराः आल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर एआईएसएफ मथुरा की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बचाने के सु ण बनाने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सभी नीतियों के साथ बहाल कराने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जेएनयू में छात्र संघ चुनावों के बाद हुए उपद्रवों की न्यायिक जांच कराने उपद्रवियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कराए जाने, निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय में अनैतिक फीस वसूल हो रही है, उसकी मनमानी पर रोक लगाने, और शिक्षा व्यवस्था के सांप्रदायिक एवं बाजारीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया।

इस प्रदर्शन में हुई सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मुनेश कुमार अकबरपुरिया ने शिक्षा का बजट कम किए जाने के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गरीब तबके से आने वाले छात्रों की पहुंच से दूर होती वैज्ञानिक शिक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रांतीय सह सचिव रवि शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर ऐसे पाठ्यक्रम छात्रों पर थोप रही है जिनका स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भाकपा मथुरा ने इसका समर्थन किया इस मौके पर पूर्व छात्र नेता श्री गफ्फार अब्बास एडवोकेट, विरेंद्र सिंह, कुल भानु कुमार और छात्र नेता इंतजार अब्बास, कृष्णा शर्मा, शुभम सागर, निखिल यादव, कुलदीप, संदीप, गौरव, राजा, अमन, दानिश आदि उपस्थित रहे।

सहकारी समितियों की हिस्सेदारी कारपोरेट को देने पर ज्ञापन

आगरा 10 अक्टूबर 2023: अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय आवाह्न पर आज सहकारिता अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन कर सहकारी समितियों के 51 प्रतिशत शेयर निजी कारपोरेट्स कंपनियों को बेचकर सहकारी समितियों में शेयर के रूप में किसानों के जमा सात हजार करोड़ से ज्यादा धनराशि को पूंजीपतियों को सौंपने के विरोध में किसान सभा जिला आगरा के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी श्री भानु चंद्र गोस्वामी को सौंपा गया।

ज्ञापन में सहकारिता अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे किसान विरोधी संशोधन को रद्द किये जाने, रबी फसल के लिए सहकारी समितियों पर सब्सिडी वाले उर्वरकों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने, तथा सहकारी समितियों पर सीमांत और लघु कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर उर्वरकों का वितरण किये जाने तथा सहकारी समितियों पर तैनात सचिव व अन्य स्टाफ को प्रति माह नियमित रूप से वेतन दिए जाने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल में किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश पूर्व प्रधान, जिलाध्यक्ष श्री भीकम सिंह कुशवाहा, जिला मंत्री श्री पूरन सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह यादव पूर्व प्रधान एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव पूरन सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

कम्युनिस्ट नेताओं की जीवनी–86

बलराज साहनी : जनवादी कलाकार और अग्रणी कम्युनिस्ट

अनिल राजिमवाले

बलराज साहनी एक उत्कृष्ट जनवादी कलाकार, वह एक प्रमुख कम्युनिस्ट थे, इप्टा के निर्माता थे और कॉमरेड पीसी जोशी के करीबी सहयोगी थे। वह फिल्मों के सुप्रसिद्ध कलाकार थे।

उनका जन्म 1 मई, 1913 को रावलपिंडी (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। उनके पिता लाला हरबंस लाल साहनी एक कट्टर आर्य समाजी थे, जिन्होंने अपना जीवन एक गरीब व्यक्ति के रूप में शुरू किया, जो कड़ी मेहनत और व्यक्तिगत ईमानदारी के माध्यम से स्थापित हो पाए। व्यवसायी थे, फिर भी वे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की तरह रहते थे।

बलराज का नाम पहले युधिष्ठिर रखा गया था लेकिन इसे बदलकर बलराज कर दिया गया क्योंकि उनके पिता की एक बहन नाम का उच्चारण नहीं कर पाती थी: उनके साथ युधिष्ठिर हमेशा 'रजिस्टर' बन जाते थे! तो, वह बलराज बन गया! उनकी माँ औपचारिक रूप से शिक्षित न होने के बावजूद रचनात्मक दिमाग की थीं। बाद में अपने जीवन में उन्होंने बलराज से उर्दू और संस्कृत भी सीखनी शुरू की! उन्हें किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं थी और दुनिया और राजनीति के बारे में उनका दिमाग खुला था।

बलराज के छोटे भाई प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी थे। उन्होंने अपना बचपन आर्य समाज के कई सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन करते हुए बिताया। उन्हें राम और लक्ष्मण की तरह एक के पीछे एक चलना होता था, एक साथ नहीं! संगीत वर्जित था।

दोनों को पारंपरिक शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। इसे सन्यासियों द्वारा चलाया जाता था, जहाँ व्याकरण के सूत्र और 'लघु कौमुदी' आदि बातें सिखाई जाती थीं। लेकिन बलराज ने जल्द ही असुविधा और असंतोष के लक्षण प्रदर्शित किए और एक दिन घोषणा की कि वह गुरुकुल छोड़ रहे हैं और नियमित स्कूल में शामिल होंगे। उसके पिता, जो एक टाइपराइटर के पीछे बैठे थे, ने कहा ठीक है। अगले ही दिन से दोनों भाई बलराज के साथ क्लास फोर में डीएवी स्कूल में पढ़ने लगे।

बलराज ने हिंदी और संस्कृत सीखी। वास्तव में, उन्हें भविष्य में एक बहु–भाषाविद् बनना था। स्कूल में रहते हुए उन्होंने हस्तलिखित एक–पत्रक पत्रिका हकीकत निकाली, जिसे व्यापक रूप से कॉपी किया गया और प्रसारित किया गया।

बलराज के प्रारंभिक वर्ष रावलपिंडी में बीते, जहां उन्होंने मैट्रिक किया, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए जिले में दूसरे स्थान पर रहे।

जब भगत सिंह को फाँसी पर चढ़ाया गया तो बलराज ने एक कविता लिखी।

स्नातक की पढ़ाई के लिए वह लाहौर गये। पिता चाहते थे कि वह कॉमर्स की पढ़ाई करें लेकिन बलराज अंग्रेजी साहित्य पढ़ना चाहते थे। उन्होंने वहां सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री अंग्रेजी साहित्य में की।

बलराज ने साहित्यिक गतिविधियों में भाग लिया और अपने अंतिम वर्ष में विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव भी बने। उन्होंने कॉलेज छात्र पत्रिका 'रवि' में विस्तार से लिखा।

वह 1934 में लाहौर से लौटे और अपने पिता के व्यवसाय में मदद की। लेकिन उन्होंने व्यवसाय की तुलना में पाठ्येतर गतिविधियाँ अधिक कीं। उदाहरण के लिए, उन्होंने घूम–घूमकर पंजाब के लोकगीतों का संग्रह किया। उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका निकालने का भी प्रयास किया। उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कश्मीरी कवि महजूर से हुई। वर्षों बाद उन्हें कश्मीर राज्य सरकार की सहायता से महजूर के जीवन पर एक फिल्म बनानी थी।

शादी

बलराज का विवाह 1936 में उनके कॉलेज शिक्षक मित्र जसवन्त राय की बहन दमयंती से हुआ। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। दमयंती को प्यार से 'दम्मो' कहा जाता था और वह बलराज की तरह अपरंपरागत थी।

वे साइकिलों पर या मालगाड़ी के खुले डिब्बों आदि में निकल पड़ते थे!

एक नई दुनिया में

पिता के कड़े विरोध के बावजूद अचानक उन दोनों ने रावलपिंडी छोड़कर लाहौर जाने का फैसला किया, लेकिन माँ अधिक शांत स्वभाव की थीं: 'लड़के को जाने दो।' बलराज ने भीष्म को कुछ व्यापारिक मामले समझाए और अगले दिन, 21 सितंबर, 1937 को दमयंती के साथ लाहौर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने साप्ताहिक 'मंडे मॉर्निंग' का प्रकाशन शुरू किया, बीपीएल बेदी, फ्रेडा बेदी और जग प्रवेश चंदर के साथ, लेकिन यह फ्लॉप हो गया। फिर उन्होंने अभिनय और लेखन में भूमिका निभाई।

जल्द ही वे कलकत्ता चले गए और एक महीने बाद उन्हें शांतिनिकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधीन शिक्षक की नौकरी मिल गई। उसी स्थान पर पुस्तक प्रदर्शनियों के माध्यम से उन्हें सेवाग्राम से एक पत्रिका 'नई तालीम' के बारे में पता चला और वे दोनों 1939 में सेवाग्राम चले गए। वहाँ वे बिजली और आधुनिक सुविधाओं के बिना, गांधीजी के आश्रम के बाहर एक मिट्टी की झोपड़ी में रहे। उन्हें गांधीजी के साथ कई बार घूमने और बातचीत करने का अवसर मिला। यह स्थान समस्त भारतीय गतिविधियों का केन्द्र था।

बीबीसी के लियोनेल फेल्डन ब्रिटेन जाते समय सेवाग्राम आये थे। उन्होंने बलराज को बीबीसी, लंदन के भारतीय

अनुभाग में नौकरी की पेशकश की, जिसे वह शुरू करने जा रहे थे। गांधीजी ने इसका अनुमोदन किया। इसके तुरंत बाद बलराज इंग्लैंड की तैयारी के लिए रावलपिंडी आये। उनका छोटा बेटा परीक्षित वहां था।

लंदन में

हिटलर ने लंदन पर बमबारी करने की धमकी दी। दरअसल, शहर पर पहला बम उसी दिन गिरा, जिस दिन बलराज और दमयंती वहां पहुंचे थे! उनका परिवार उनके जाने के खिलाफ था। बलराज कमाई के लिए नहीं बल्कि यूरोप का अनुभव पाने के लिए बीबीसी के लिए काम करना चाहते थे।

भारत स्थित उनकी माँ, बमबारी के बीच समाचार पाने और उनकी आवाज सुनने के लिए रेडियो के पास बैठी रहती थीं। उस दिन से लेकर लंदन में उनके आखिरी दिन तक, उनकी माँ सप्ताह में दो बार बैठती थीं बलराज की आवाज सुना करतीं और बातें करती थीं। बलराज को युद्ध के कारण कोवेंट्री में स्थानांतरित कर दिया गया था। ब्रिटेन में उनके पूरे प्रवास के दौरान रेडियो की सुई एक ही स्थान पर खड़ी रही। बीबीसी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के साथ काम किया।

ब्रिटिश कम्युनिस्टों से मुलाकात

ब्रिटेन में रहते हुए बलराज ने मार्क्स और लेनिन की मौलिक कृतियों का गहन अध्ययन किया। वह और दमयंती दोनों सीपीजीबी के नेताओं के संपर्क में आये। बेन ब्रैडली ब्रिटेन में भारतीय साथियों की देखभाल करते थे। उन्होंने पीसी जोशी को लिखा कि दमयंती एक अच्छी और स्थिर कामरेड थीं जबकि बलराज एक उत्साही व्यक्ति थे। वास्तव में, दमयंती बलराज की जानकारी के बिना भी सबसे पहले पार्टी में शामिल हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि वह बहुत बोहेमियन हैं! ब्रैडली ने उनसे अगली बैठक में उन्हें लाने के लिए कहा और इस तरह बलराज का भी नामांकन हो गया।

भारत लौटना

बलराज और दमयंती 1944 में

रावलपिंडी लौट आए। बलराज अब बहुत अलग व्यक्ति थे, अधिक आत्मविश्वासी और स्पष्ट। उन्होंने विभिन्न दलों की सार्वजनिक बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) से एक अच्छे पद का प्रस्ताव मिला।

उनके पुराने मित्र चेतन आनंद के आने का मौका निर्णायक मोड़ बन गया, जो गोर्की की 'लोअर डेप्थ्स' पर आधारित एक फिल्म का निर्माण करना चाहते थे। बलराज तुरंत दमयंती और उनके दोनों बच्चों को लेकर बंबई के लिए रवाना हो गए। वे चेतन, देव आनंद, गोल्डी और अन्य लोगों के साथ एक ही घर में रहते थे। बलराज और दमयंती अपने परिचय पत्र के साथ उनकी सचिव पार्वती (कृष्णन) के माध्यम से पीसी जोशी से मिलने गए। यह पूछे जाने पर कि वे कमाई कैसे करेंगी, दमयंती ने कहा कि वह पहले ही पृथ्वी राज कपूर के पृथ्वी थिएटर्स से जुड़ चुकी हैं। बलराज ने अपना पहला चेक कम्युनिस्ट पार्टी को समर्पित कर दिया।

जल्द ही बलराज का संपर्क जुबैदा जैसे इप्टा के दिग्गज प्रोड्यूसर के ए अब्बास से हुआ। बलराज जल्द ही इप्टा के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। अकेले बंबई में, विभिन्न इलाकों में 'मैं कौन हूं' के 300 से अधिक प्रदर्शन हुए। एक बार जब उनके पिता उन्हें ले जाने के लिए मनाने आए, तो वह इससे बहुत प्रभावित हुए। इप्टा का कार्यक्रम देखकर उन्होंने बलराज अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दिया।

इस बीच, 1946 में डायरिया की गलत दवा से दमयंती की मृत्यु हो गई। पृथ्वी राज कपूर की 'दीवार' में उनका अभिनय यादगार था।

बलराज ने 'धरती के लाल', 'गुड़िया' आदि में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बहन संतोष से दूसरी शादी की। 'हम लोग' और 'दो बीघा जमीन' से उन्हें प्रसिद्धि मिली। दो बीघा जमीन

शेष पेज 15 पर...

आर्थिक संकट दिखाता है रोजगार सृजन में गिरावट

डॉ. ज्ञान पाठक

2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार सत्ता संभालते वक्त जो बेरोजगारहीनता का वक्त था वह नियमित रोजगार सृजन में ठीक–ठाक कमी होने के कारण बद से बदतर होता जा रहा है। उच्च मूल्यवृद्धि और मुद्रास्फीति के साथ मिलकर यह बेरोजगारी की परिस्थिति लोगों को अभूतपूर्व आर्थिक संकट में डाल रही है जिससे तथाकथित आर्थिक विकास बढ़ने की बजाय स्व–रोजगार बढ़ा जिस पर सरकार डींग हांक रही है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एकदम हालिया अध्ययन ''स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023''(भारत में रोजगार की स्थिति) कहता है कि वृद्धि के धीमी होने और महामारी के कारण नियमित वेतन वाले रोजगार सृजन घटे हैं। 2017 से लैंगिक आधारित विषमताएं मजबूत हुई हैं, तब आदमियों की तुलना में 76 प्रतिशत महिलाएं वेतन कमा रही थीं।

अध्ययन के अनुसार, वृद्धि और अच्छी नौकरी के बीच जुड़ाव बना हुआ है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि ''तेजी से वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां जरूरी नहीं है कि तेज रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करें''। सम्मानजनक रोजगार वृद्धि 2004 और 2019 के बीच तेज थी, इसके साथ ही नियमित वेतन या नौकरी वाले काम आदमियों के लिए 18 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गए थे और महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गए थे। फिर भी, 2019 से, औरतों के लिए नियमित वेतन या नौकरी वालों काम दोनों ही गिरकर 20 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं।

उत्तर–कोविड महामारी में स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 15 प्रतिशत बनी हुई है और ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति 25 वर्ष से कम उम्र वाले स्नातकों की एक बड़ी संख्या 42 प्रतिशत है।

2004 से गिरने के बाद या स्थिर महिला रोजगार दर या (महिलाओं की सहभागिता दर) 2019 से बढ़ी है, लेकिन गलत कारणों से। 2019 से महिलाओं की सहभागिता दर के इस बढ़त का कारण स्वरोजगार रहा है जिसका कारण आर्थिक संकट रहा है न कि आर्थिक वृद्धि। कोविड से पहले, 50 प्रतिशत महिलाएं स्वरोजगार थीं। कोविड के बाद यह बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। परणिामस्वरूप, स्वरोजगार से कमाई वास्तविक अर्थो में इस अवधि में गिरी है। यहां तक कि 2020 के लाकडाउन के दो साल बाद भी, स्वरोजगार कमाई केवल 85 प्रतिशत थी जो कि अप्रैल–जून 2009 के तिमाही में थी।

अध्ययन में पाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एन्टरप्रेन्यूरशिप अभी तक दुर्लभ है। जिन फर्मो में 20 से ज्यादा व्यक्तियों के पास रोजगार है उनमें दुर्लभ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से उद्यम स्वामी हैं। इसी तरह फर्म या कंपनी के बढ़ते आकार के साथ उच्च जाति का उच्च प्रतिनिधित्व है।

2019 पूर्व आर्थिक वृद्धि ने लोगों को खेती से बाहर निकाला और नियमित वेतनभोगी वर्कर्स का हिस्सा बढ़ गया। लेकिन महिलाओं ने श्रम बल छोड़ दिया जो अनियमित स्तर पर चिंता बनी हुई हैं। हालांकि गैर कृषि रोजगार का हिस्सा बढ़ा, लेकिन इसकी बढ़त नियमित वेतन रोजगार या संगठित क्षेत्र में रोजगार के बढ़त के जैसे नहीं थी।

जाति विश्लेषण दिखाता है कि अन्यों के मुकाबले अनुसूचित जाति वर्कर अनियमित रोजगार में कहीं अधिक हैं। 2021–22 के अनुसार, अनुसूचित जाति के 22 प्रतिशत नियमित वेतन पर थे जबकि नियमित वेतन पर अन्य 32 प्रतिशत थे। फिर भी, 13 प्रतिशत अन्य की तुलना में अनुसूचित जाति के 40 प्रतिशत वर्कस अनियमित रोजगार में थे। अनुसूचित जाति से वर्कर बढ़ती संख्या में कृषि से निर्माण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं जो कि अनियमित रोजगार का मुख्य स्रोत बना हुआ है।

अध्ययन बताता है कि सभी धर्मो के मुकाबले लैंगिक और जाति पहचानों में रोजगार संरचना कहीं अधिक भिन्न है। यहां यह नोट करने लायक है कि पूरे चार दशकों के दौरान मुसलमान शिक्षा, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिस्थिति एवं अन्य प्रांसगिक कारकों के मद्देनजर नियमित रोजगार पकड़ना कम पसंद करते हैं और अधिकतर स्वयं का रोजगार (स्वरोजगार) या अनियमित दिहाड़ी मतदूरी पर काम करते हैं, यहां यह याद किया जा सकता है कि नियमित रोजगार में सतत अल्प प्रतिनिधित्व को 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट में भी उल्लेखित किया गया था। अध्ययन में जोर दिया गया है कि यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।

भारत में कृषि क्षेत्र में, रोजगार की तुलना उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ा, जिसके कारण रोजगार लोच में स्थिर गिरावट आई, जो कि विकासशील देश औसत की तुलना में बहुत नीचे है। सबसे हालिया अवधि (2017–2021) इस ट्रेंड का एक अपवाद है। वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से धीमी हुई लेकिन रोजगार तेजी से बढ़ा। इस सरकार आंकड़ों के हिसाब से इस अध्ययन ने नतीजा निकाला कि वृद्धि और रोजगार असहसंबद्धित रहा है। तथापि, अन्य स्रोतों को स्वयं के आंकड़ों पर ही संदेह है और उन्होंने आंकड़ों पर सवाल उठाया है कि जब आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है तो रोजगार कैसे बढ़ सकता है? हां, यह देश में त्रुटिपूर्ण ढंग से रोजगार और बेरोजगारों की गणना से ही हो सकता है।

शिक्षित युवकों के लिए बेरोजगारी का परिदृश्य तंग करने वाला है, अध्ययन बताता हैं कि 25 वर्ष से कम उम्र वालों के बीच बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वे) 2021–22 के आंकड़ों को उद्धृत करते हुए अध्ययन में रेखांकित किया गया कि अशिक्षितों के बीच बेरोजगारी दर 13.5 प्रतिशत, शिक्षित लेकिन प्राथमिक शिक्षा से नीचे बेरोजगारी दर 10.64 प्रतिशत, प्राथमिक और माध्यामिक शिक्षा तक बेरोजगारी 15 प्रतिशत, उच्चतर शिक्षा तक बेरोजगारी 18.1 प्रतिशत, हायर सेकेंडरी तक बेरोजगारी 21.4 प्रतिशत, स्नातक और इससे ऊपर 42.3 प्रतिशत बेरोजगारी है।

हायर सेकेंडरी शिक्षा वाले 25 से 29 वर्ष के युवाओं के बीच बेरोजगारी 10.6 प्रतिशत और इस उम्र के स्नातक और इससे अधिक शिक्षा वालों के बीच बेरोजगारी दर 22.8 प्रतिशत है। यहां तक कि 30 साल से लेकर 34 साल के स्नातक और इससे अधिक शिक्षितों के बीच 9.8 प्रतिशत जैसी उच्च बेरोजगारी दर है।

यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है यद्यपि स्नातक यदि नौकरी पाते हैं, तो उस नौकरी की प्रकृति क्या है और क्या ये नौकरियां उन युवाओं की आकांक्षाओं और कौशल से मेल खाती है। अध्ययन का सुझाव है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अधिक अध्ययन की जरूरत है।

मांग और आपूर्ति की और से चुनौतियों के कारण भारत में अधिकांश औरतें श्रम बल के बाहर रहती हैं। महिला श्रम बल सहभागिता दर (फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट–संक्षेप में एलएफपीआर) देश के लगभग सभी राज्यों में लाभ की रेखा से नीचे है।

महिला एलएपीआर का जो पूर्वानुमान किया गया है वह उनके सकल घरेलू उत्पाद के प्रति व्यक्ति स्तर से नीचे है। यहां तक यदि लैंगिक मानदंड बदलते हैं और महिलाओं के लिए वैतनिक काम अवरोध नहीं बनते–फिर भी सवाल उठता है कि क्या पर्याप्त नौकरियां हैं। यह अध्ययन कई साक्ष्यों को दिखाता है जो कि महिला एलएफपीआर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे है।

2017 और 2021 के बीच नियमित वैतनिक नौकरियों (लिखित अनुबंध और लाभ) के सृजन में मंदी थी नियमित वैतनिक नौकरियों के हिस्से के रूप में यह 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हुआ। 2020–21 महामारी वाले वर्ष में वैतनिक रोजगार 22 लाख तक गिर गया। लेकिन यह कुल बदलाव औपचारिक रोजगार में 30 लाख की बढ़त छिपाता है और सेमी अनौपचारिक वैतनिक नौकरियों में 52 लाख नौकरियां छूटीं। यद्यपि आधे से ज्यादा रोजगार छूटने का मामला औरतों का रहा है, औपचारिक रोजगार में केवल बढ़त का एक तीसरा अंश महिलाओं को प्राप्त हुआ। इसलिए, कुल मिलाकर, इस अवधि में महिलाएं औपचारिक रोजगार से बाहर हुईं। न केवल यह हुआ, बल्कि आर्थिक संकटों के कारण स्वरोजगार की ओर बदलाव हुआ।

एनएफआईआरटीडब्लू का दो दिवसीय 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन

जयपुर, 5 अक्टूबर 2023: नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (एनएफआईआरटीडब्लू) का दो दिवसीय 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22–23 दिसंबर 2023 को कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलोर में होगा। अमरजीत कौर, राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) 22 दिसंबर 2023 को प्रात10 बजे सम्मेलन के खुले सत्र का उद्घाटन करेगी।

एनएफआईआरटीडब्लू का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 22 अक्टूबर 2016 को पंजाब राज्य के मोगा शहर में हुआ था।

आगामी सम्मेलन में 18 राज्यों के राजकीय सडक परिवहन उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के बस, लॉरी, टैक्सी कार, ऑटो रिक्शा श्रमिकों के 37 संगठनों के 300 प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

इस सम्मेलन के मेजबान 'केएसआरटीसी स्टाफ एवं वर्कर्स फेडरेशन' द्वारा सम्मेलन की सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जायेंगी, जिनमें प्रतिनिधियों के लिये 21 से 24 दिसंबर 2023 तक चार दिवस की आवास व्यवस्था एवं 22 से 24 दिसंबर 2023 तक तीन दिवस की भोजन सुविधा भी शामिल है।

सभी सम्बद्ध संगठनों एवं सम्मेलन के अवसर पर सम्बद्ध किये जाने वाले नये संगठनों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या आवंटित की जा चुकी है। प्रतिनिधि शुल्क रुपये 500 निर्धारित किया गया है।

सम्मेलन के मेजबान संगठन के महासचिव विजय भाष्कर डीए के अनुसार प्रारंभिक तैयारियां शुरु की जा चुकी हैं एवं सम्मेलन को उत्कृष्ट तरीके से आयोजित करने के लिये मेजबान संगठन के अध्यक्ष एच. वी. अनंतसुब्बा राव, जो एनएफआईआरटीडब्लू के भी अध्यक्ष हैं, के मार्गदर्शन में शीघ्र एक स्वागत समिति गठित की जायेगी।

मेजबान संगठन द्वारा सम्मेलन से एक दिवस पूर्व 21 दिसम्बर 2023 को सांयकाल बंगलोर में सडक परिवहन श्रमिकों की एक विशाल रैली आयोजित की जायेगी।

एनएफआईआरटीडब्लू सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों खंडों के सडक परिवहन श्रमिकों का शीर्ष संगठन है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य देश में बेहतर यात्री सडक परिवहन प्रणाली एवं बेहतर माल सडक परिवहन प्रणाली और सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के श्रमिकों की बेहतर सेवा शर्तो के लिये कार्य करना है। यह एकता एवं संघर्ष की नीति में विश्वास रखता है।

मोदी की जाति राजनीति, प्रतिशोध है गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ

आरएसएस की हिन्दुत्व सोच से बंधे हैं प्रधानमंत्री

अरुण श्रीवास्तव

अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निर्मम हमले, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के विरूद्ध केंद्रीय एजेंसियों को छोड़ना और उत्पीड़ितों की लंबी सूची में हाल में जुड़ा है पत्रकारों पर हमला, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने अतीत से बदला ले रहे हैं। जब तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ थे, राजनीतिक दायरों में उनका कोई नाम नहीं था और यहां तक कि स्वयं उनकी पार्टी के लोग उनके साथ बराबरी और परानुभूति के साथ व्यवहार नहीं करते थे।

यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, मोदी ने पार्टी के पिता तुल्य नेता एल.के. आडवाणी को एक किनारे कर दिया था और मुरली मनोहर जोशी और अन्य नेताओं के महत्व को घटा दिया। वैसे ही मायावती को यह विचार नापसंद था कि किसी को उसका प्रतियोगी देखा जाए, मोदी का मामला भी ऐसा ही है।

यह कुछ अनोखा नहीं है। मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि वाला आदमी हमेशा अपनी राजनीतिक अस्तित्व के संभावित खतरे और चुनौती के बारे मे संदेह करता है। कोई भाजपा नेता सामने बोल नहीं सकता और उन्हें बुद्धिमानी से सलाह नहीं दे सकता। कोई भी नेता ऐसा करने की कोशिश करता है उसे मोदी की शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए खतरा समझा जाता है।

मोदी अपनी स्वर्णिम खामोशी के लिए जाने जाते हैं। मोदी किसी भी राष्ट्रीय महतव के किसी भी मुद्दे पर बोलना नहीं पसंद करते। मोदी को भय है कि उनके शब्द समुचित और सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, उनकी छवि, जो कि उन्होंने मेहनत और लगातार प्रयासों से तैयार की है, वह नष्ट हो जाएगी। उन्होंने मणिपुर के मामले में कुछ नहीं बोला जबकि मणिपुर गृहयुद्ध के कगार पर था और अभी भी घातक हिंसा की जकड़ में है। वे जानते है कि मणिपुर पर मुंह खोलना उनकी प्रतिष्ठा और छवि को खतरे में डाल सकता है। आरएसएस और हिन्दू समर्थक नाराज हो जाएंगे और अन्ततः वे अपना समर्थन आधार खो देंगे जिसके आधार पर वे सत्ता का आनंद ले रहे हैं।

उनकी खामोशी उनकी वास्तविक मंशाओं और दुविधाओं को छिपाने में असमर्थ हैं। भाजपा इकोसिस्टम और उनके भक्तों ने उनकी खामोशी को कुछ अन्य अर्थों में व्याख्या की हो, वैश्विक बन्धुत्व जान चुका है और यह कारण था कि अधिकांश विश्व मणिपुर के बारे में बहुसंख्यक हिन्दू मैइती और मुख्यतः ईसाई नागा और कुकी आदिवासियों के बीच अशांति के बारे में चुप रहा।

भारतीय जनतंत्र का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व को बढ़ावा देना है, लेकिन मोदी की प्राथमिकता इन तीन तीनों आदर्शों को व्यवहार में लाने की नहीं है। उनके लिए ये आदर्श एक नए राजनीतिक घटक को बढ़ा सकते हैं, एक नए नेता को जो कि उनके वर्चस्व को चुनौती दे सकता है।

विपक्ष के नेताओं को चुप कराना और यंत्रणा देना उनकी कार्यशैली का अभिन्न अंग है। दो अन्य कारक अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं: उनका गुजरात से और ओबीसी समुदाय से होना। भारतीय राजनीति परंपरिक रूप से उत्तर भारत के नेताओं के प्रभुत्व और नियंत्रण में हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश से।

उन्हें जगह देना मोदी के लिए मुसीबत को न्यौता देना जैसा होता। मोदी ने उन्हें अपने अधीन रखना पसंद किया। मोदी ने ओबीसी और दलित राजनीति खेली, लेकिन आरएसएस की यह योजना कि उन्हें हिन्दुओं के बतौर देखना यह मोदी के हाथ बांधता है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने अपना स्वतंत्र रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस की रणनीति को पार नहीं कर सके। मुख्यतः इस कारण, ओबीसी के बीच वह अपना मजबूत आधार तैयार नहीं कर सके, न ही हिन्दू मुख्यधारा में उन्हें मिला पाए।

यह एक खुला राज है कि वे निर्ममता से ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि विपक्ष के नेता मोदी और उनके नेतृत्व के खिलाफ आवाज न उठाएं। उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान गुजरात ने जघन्य हत्याकांड देखा था जिसमें लगभग 2,000 मुसलमान हिन्दू कट्टरपंथियों और किराये के टट्टुओं द्वारा मारे गए थे, उन्होंने पुलिस बल की उपयोगिता की प्रभावकारिता को जान लिया था।

2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जब विपक्षी ताकतें और पार्टियों ने उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, मोदी ने प्रभावशाली ढंग से उनके खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यह एक ज्ञात तथ्य है कि पुलिस बल का ध्रुवीकरण हआ है और सबसे बुरा सांप्रदायीकरण दिल्ली पुलिस का हुआ है। मोदी ने वास्तव में केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की स्थिति को हिटलर की गेसटापो सदृश बना दिया।

मोदी के पुलिस को इस्तेमाल करने पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी और निष्क्रिय रवैया उनके शासन के लगभग छः साल तक रहा। राहुल गांधी के 'भारत जोड़ो यात्रा' को संगठित करने के बाद सड़कों पर उनकी जड़ता टूटी। एक अच्छी–खासी संख्या में शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई। इन सालों में उनकी निष्क्रियता और यंत्रणा का भय उनकी चुप्पी में झलकता है। ये लोग यहां तक कानूनी मदद लेने में भी डर रहे थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया ईडी स्वयं में कानून की तरह काम नहीं कर सकता लेकिन उनके आक्रोश और सरोकार को व्यापक समर्थन नहीं मिला।

तीन साल पहले 84 वर्षीय झारखंड के आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की जेल में मृत्यु हुई। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं ने इस सवाल को उठाया, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक लोगों की चेतना को झकझोर न सका। स्वामी पर्किसन के मरीज थे जिन्हें बेहद जरूरी सुविधाओं से वंचित रखा गया था–उन वंचित चीजों में से उन्हें सीपर (स्ट्रा) से पानी न पीने देना भी था। खास बात है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड राज्यपाल कार्यभार के दौरान उन्हें एक धर्मनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर जानती थी। स्टेन स्वामी गांधीवादी विचारों के थे।

तथापि, केवल कल ही सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ईडी पर फटकार लगाई और आरोप लगाया कि वह ''स्वयं में एक कानून की तरह व्यवहार'' कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को निष्पक्षता, गैर प्रतिशोधी और सत्यनिष्ठा के मानकों को अपने काम में लाने के लिए कहा। ईडी की यह प्रैक्टिस कि वे आरोपी को उस पर लगे आरोपों को नहीं बताएंगे, को भी सर्वोच्च न्यायालय ने सवालों के घेरे में लिया। यह गंभीर अपवाद है कि ईडी अधिकारी आरोपी को मुंहजुबानी आरोप बताते हैं उन्हें उनकी गिरफ्तारी के आधार की लिखित कॉपी के बिना।

पीठ ने कहा कि यह ''ईडी के बारे में बहुत कुछ कहता है और दिखाता है कि उनकी कार्यशैली खराब है, खासतौर से जब एजेंसी को देश की वित्तीय सुरक्षा संरक्षित करने का जिम्मा मिला हुआ है।'' पीठ ने आगे कहाः ''ईडी को जवाबदेह होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए और निष्पक्षता के उचित मानकों को मानना चाहिए और अपने फैसले में प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए।

पूरे देश भर के लिए नियमों को लिखते हुए, पीठ ने कहाः ''हम मानते हैं कि गिरफ्तारी के आधार की एक कॉपी आरोपी को गिरफ्तार करते समय जरूर देनी चाहिए।'' कोर्ट ने माना कि यह अनुच्छेद 22(1) के तहत संवैधानिक अधिकार है चूंकि यह आरोपी को गिरफ्तारी की लिखित शिकायत के आधार पर कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है। बेशक यह निर्णय एम थ्री एम रियल स्टेट ग्रुप के निदेशकों–पंकज बसंल और बसंत बंसल की याचिका पर आया, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने धन–शोधन कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

लेकिन इस निर्णय से सामाजिक ओर राजनीति कार्यकर्ताओं को भारी राहत मिली है जो कि देश भर में मोदी ओर उसकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निशाने पर लिए गए थे। यह रेखांकित करते हुए कि ''ईडी से अपने कार्य व्यवहार में प्रतिशोधी की उम्मीद नहीं की जाती है'', सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला दिया कि एजेंसी आरोपी को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का लिखित आधार दे।

एक और समानता है मोदी और मायावती के बीच, जाटव जो कि मायावती के मुख्य समर्थक हैं, उन्होंने अपना समर्थन मायावती को दिया, फिर भी वे आहत महसूस करते हैं कि मायावती ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसा ही मामला मोदी के साथ है। उन्होंने भी ओबीसी के लिए वास्तविक रूप से कुछ नहीं किया। जाति सर्वे ने उन्हें ओबीसी की ताकत का आकलन करने का मौका दिया। लेकिन आरएसएस के आदेश पर मोदी ने ओबीसी के रास्ते को छोड़ दिया। चूंकि यह आरएसएस की हिन्दुत्व राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा और आरएसएस की इस योजना को रोकेगा कि वह भारत के 80 प्रतिशत हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे मानकर, मोदी ने पूरी तरह ओबीसी, ईबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय के लाभों से इनकार कर दिया है। यह समझ से बाहर है कि ओबीसी और ईबीसी का एक महारथी इस मूल तथ्य को कैसे भूल सकता है कि राजनीति और आर्थिक वर्चस्व अमीर और सामंती लोगों के शोषण के सबसे बड़े उत्पीड़ित गरीब और दलित हैं।

मोटे अनाज के आटे पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला वापस ले सरकार

पटना, 10 अक्टूबर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने मोटे अनाज के आटे पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले की निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार से मोटे अनाज के आटे के साथ साथ सभी प्रकार के चावल, दाल और आटे पर से जीएसटी हटाने की मांग की है।

भाकपा राज्य सचिव ने बयान जारी कर कहा कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। पिछले साल ही चावल, आटे सहित कई उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी लगाये गए थे जिससे महंगाई बढ़ गई है। अब सरकार ने मोटे अनाज के आटे पर भी पांच फीसदी जीएसटी लगा दी है जिससे आटे की कीमत बढ़ेगी और केंद्र सरकार के मोटे अनाज को बढ़ावा देने के अभियान को भी झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ मोटे अनाज के आटे पर पांच फीसदी जीएसटी लगा दी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कड़े शब्दों में इसका विरोध करती है। मोटे अनाज का उपयोग अधिकतर गरीब लोग हीं करते हैं। देश की जनता पहले से हीं महंगाई से तबाह है, इसके वाबजूद सरकार ने आटे पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया। इस फैसले से महंगाई बढ़ेगी और गरीबों को दो जून की रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने केन्द्र सरकार से आटे, चावल और दाल पर से पांच फीसदी जीएसटी वापस लेने की मांग की।

बिहार पहुँची 'ढाई आखर प्रेम' पदयात्रा

देश के सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पदयात्रा 7 अक्टूबर 2023 से बिहार में होगी। 'ढाई आखर प्रेमः राष्ट्रीय सांस्कृतिक जत्था' के अंतर्गत बिहार का नाट्यकर्मी, लेखक, कवि, अभिनेता, गायक और सामजिक कार्यकर्ता पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के अंतर्गत नाटक, गीत, नृत्य और लोकप्रिय संवाद प्रस्तुत किये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि इप्टा ने पिछले साल आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर 'ढाई आखर प्रेमः सांस्कृतिक यात्रा' की शुरुआत 9 अप्रैल 2022 को रायपुर छत्तीसगढ़ से की थी। इस यात्रा में इप्टा ने अपने नाटकों, गीतों, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के 300 से अधिक गांवों, कस्बों, शहरों में आत्मीय संबंध स्थापित करते हुए प्रेम, समन्वय, सौहार्द और एकजुटता का संदेश दिया गया। यात्रा का समापन 22 मई 2022 को इंदौर में हुआ।

डाल्टनगंज (झारखंड) में हुए इप्टा के राष्ट्रीय अधिवेशन ने फैसला लिया कि भगत सिंह के जन्मदिन 28 सितंबर 2023 से पूरे देश में 'ढाई आखर प्रेमः राष्ट्रीय सांस्कृतिक जत्था' पदयात्रा की जाएगी, जिसका समापन महात्मा गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में होगा।

जत्था का बिहार पड़ाव 7 से 14 अक्टूबर 2023 तक पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) में निर्धारित है। 7 अक्टूबर को बाँकीपुर जंक्शन (वर्तमान में पटना जंक्शन), जहाँ 1917 महात्मा गाँधी पहली बार बिहार आए और चम्पारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, से पदयात्रा की शुरुआत होगी। गाँधी मैदान के समीप भगत सिंह और महात्मा गाँधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत भिखारी ठाकुर रंगभूमि, दक्षिणी गाँधी मैदान में सांस्कृतिक प्रस्तुति की जायेगी।

8 अक्टूबर को महात्मा गांधी के मुजफ्फरपुर पड़ाव और निलहे आन्दोलन की कर्मभूमि चम्पारण के जसौली पट्टी से ढाई आखर प्रेम की पदयात्रा की जायेगी। प्यार, मोहब्बत और इन्सानियत का संवाद करते, गीत गाते, उनकी सुनते, अपनी सुनाते, बतख मियां की बात बताते हुए 8 से 14 अक्टूबर 2023 की शाम को गाँधी स्मारक संग्रहालय (मोतिहारी) समाप्त होगी।

पदयात्रा का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2023 को भिखारी ठाकुर रंगभूमि, गांधी मैदान में होगा और 8 अक्टूबर 2023 को जसौलीपट्टी (मोतिहारी) में सांस्कृतिक संध्या होगी। पदयात्रा के शुभारम्भ के अवसर पर गाँधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नाटक और जनगीत प्रस्तुत होंगे। संस्कृतिकर्मी, साहित्यकार और सामजिक कार्यकर्ता सहित दर्जन भर सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं का जुटान होगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण छआया नाचा लोक नाट्यशैली की प्रस्तुति होगी। सीताराम सिंह के नेतृत्व में जनगीतों की प्रस्तुति होगी।

जत्था में शामिल कलाकारों ने चंदेरी के बुनकरों और श्रमिकों से किया संवाद

चंदेरीः प्रेम, सद्भाव और एकजुटता को लेकर देशभर में चल रही "ढाई आखर प्रेम" की सांस्कृतिक यात्रा का 04, अक्टूबर, 2023 को अशोकनगर के चंदेरी शहर में आगमन हुआ। यह यात्रा भगतसिंह के जन्मदिवस 28 सितंबर, 2023 से शुरू होकर गांधी जी के शहादत दिवस 30 जनवरी, 2024 तक चलेगी। चंदेरी शहर सदियों से श्रम से जुड़ा हुआ है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। चंदेरी शहर बुनकरों और श्रमिकों का केंद्र है। जिस जुलाहे कबीर ने अपने चरखे से श्रम और अपने पदों से प्रेम का संदेश दिया उसी संदेश को लेकर यह यात्रा चंदेरी के आम कामगारों और मेहनतकशों के बीच पहुंची और उनसे संवाद किया।

यात्रा का प्रारंभ शहर के बीचों बीच स्थित जयस्तंभ पार्क से हुआ। यहां विनीत तिवारी ने चर्चा करते हुए यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। इसके बाद जत्था हैंडलूम पार्क गया। जत्था के साथ चल रहे स्थानीय बुनकर फारूख ने बताया कि यहां के हैंडलूम सामूहिक हैं जो उन श्रमिकों के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं जिनके पास हथकरघा लगाने के लिए घर में पर्याप्त जगह नहीं है। उन्होंने इन श्रमिकों की समस्याएं और उनके रोजगार को लेकर बातचीत की।

शेष पेज 9 पर...

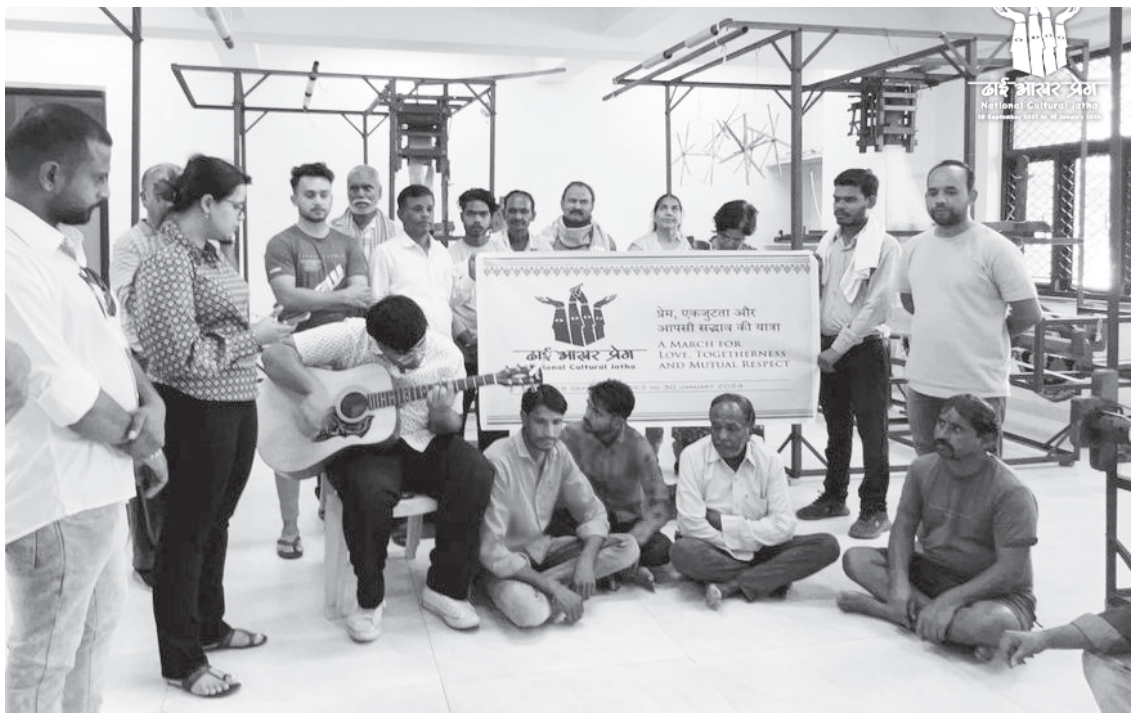

छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चांपा में ''ढाई आखर प्रेम'' यात्रा

चांपाः प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, एकजुटता की भावना के साथ ही देश की बहुलतावादी संस्कृति का सम्मान करने वाले जनसंगठनों के नेतृत्व में देशभर में ढाई आखर प्रेम यात्रा के नाम से सांस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है। भगत सिंह के जन्मदिवस पर अलवर से शुरू हुई यह यात्रा 03 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चांपा में निकाली गई।

बच्चे, बड़े सभी के हाथों में प्रेम का संदेश देते पोस्टर, कार्डबोर्ड, ढपली की तान के साथ जनगीत गाते इप्टा के साथी और उनके साथ चल रहे आम नागरिक। जांजगीर की बात करें तो पिछली बार की तुलना में यह यात्रा ज्यादा व्यवस्थित और नयेपन के साथ थी। सुबह ही बारिश हो चुकी थी, जिसके चलते मौसम भी सुहाना था, लेकिन जैसा कि छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज है कि बरसात के दिनों में कितनी भी बारिश हो जाये, कुछ ही देर में उमस अपना स्थान बना लेती है। फिर भी पिछली बार की जानलेवा तपन से तो बेहतर मौसम था। पिछली बार जैसे ही हम लोग जांजगीर पहुंचे गन्ने का रस पिला कर स्वागत किया गया था। इस बार उसकी जरूरत नहीं पड़ी। गन्ने का रस मिलने वाली जगह पर मूंगफली और कच्चे सिघाड़े के ठेले लगे थे।

खैर, यात्रा की शुरुआत तालाब के किनारे लगभग हजार साल पुराने मंदिर के परिसर पर गीतों और संबोधन के साथ हुई। मै जब पहुंचा तब तक यहां का लोकगीत जिसे बांसगीत कहते हैं, वरिष्ठ लोकगायक द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका था। जिसकी प्रशंसा बाद में भी सुनने को मिली। मंदिर परिसर से रैली के रूप में आगे बढ़ने की तैयारी हो चुकी थी। इप्टा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मणिमय मुखर्जी माइक थाम चुके थे और मिल के चलो–मिल के चलो जनगीत फिजा में गूंज रहा था और यात्रा बढ़ चली। इप्टा रायगढ़ के साथी भरत और श्याम सहित अन्य साथी भी ढपली के साथ जनगीत गाते हुए सभी के साथ कदमताल करते हुए चलते रहे। सांस्कृतिक रैली में पारंपरिक वेशभूषा में सजे–धजे लड़के लड़कियां। प्रेम और शांति का नारा लगाते हुए सभी साथी कचहरी चौक पहुंचे। यहां पर शहीद पार्क के बाहर जनगीतों की प्रस्तुति के साथ ही यात्रा के उद्देश्य को लेकर बातें रखी गयी।

इस दौरान इप्टा के साथी व छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी अध्यक्ष ईश्वर सिंह दोस्त ने कहा कि जब परिवार, समाज में शक–ओ–शुबहा की शुरुआत होती है तो परिवार और समाज टूटता है। इसी तरह देश और दुनिया। लेकिन आज यह सब जानते हुए भी कुछ लोग शक–ओ–शुबहा को फैलाते–फैलाते यहां तक आ पहुंचे हैं कि बाकायदा नफरत के करोबार में तत्परता के साथ लगे हुए हैं। वो नफरत इसलिये फैला रहे हैं ताकि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों को लेकर आवाज ना उठायें। आपस में लड़ते–भिड़ते रहें। उन्होंने कहा कि इप्टा इसीलिए प्रेम की यात्रा निकाल रही है ताकि समाज से नफरत गायब हो और परस्पर प्रेम बढ़े। इप्टा उसी उसी संदेश को आगे बढ़ा रही है जो बुद्ध ने संदेश दिया था। बुद्ध, कबीर, रहीम, रसखान, नानक जैसे हमारे पूर्वजों ने जो यात्रा शुरू की थी, आज इप्टा उसी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।

यात्रा के क्षेत्रीय आयोजक जीवन यादव का उत्साह पहले की तरह ही देखने को मिला। स्पीकर खराब होने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है, जो दिख भी रहा था। जीवन यादव ने कहा कि यह यात्रा श्रम से उपजे प्रेम की यात्रा है। यहाँ पर जसम रायपुर के साथी राजकुमार सोनी ने जनगीत प्रस्तुत किया। इप्टा बिलासपुर से अरुण दाभाड़कर, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नथमल शर्मा, रफीक खान, मोहम्मद रफीक सहित श्रीकांत वर्मा पीठ के अध्यक्ष राम कुमार तिवारी, श्याम बिहारी बनाफर, मुदित मिश्र सहित क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

पेज 8 से जारी...

वास्तव में इन बुनकरों काम बेहद बारीक, मेहनती और जोखिम भरा है। यहां के कारीगर एक–एक धागे को सहज कर ताने–बाने से कई घंटो में कपड़ों का निर्माण करते हैं। लेकिन बीच में बिचौलियों के हस्तक्षेप और सरकार द्वारा इनके रोजगार की सुरक्षा न होने से इनको श्रम के अनुसार दाम नहीं मिल पाता। जत्था के साथियों ने इन कामगारों से विस्तृत संवाद करके इनके बीच कबीर को याद किया। सत्यभामा और कबीर ने कबीर का गीत "झीनी बीनी चदरिया" गाया। वहीं विनीत तिवारी ने बुनकरों से कहा कि जिस तरह आप ताना–बाना जोड़कर सुंदर, रंगीन और मजबूत कपड़ा बुनते हैं उसी तरह हमें बिना किसी के बहकावे में आए समाज को जोड़े रखना है। जाति और धर्म के बंधनों के इतर एक–दूसरे से प्रेम करते रहना है। इसके बाद जत्था के साथियों ने स्थानीय लोगों से चर्चा की। इस समय सत्यभामा और कबीर राजोरिया ने कबीर का गीत "होशियार रहना रे" और हरिओम राजोरिया का गीत "चल चला चल" का गायन किया। विख्यात चित्रकार पंकज दीक्षित ने यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि नफरत जितनी तेजी से फैलती है उतनी तेजी से प्रेम नहीं फैलता। लेकिन हमें कोशिश करते रहना होगा और परस्पर भाईचारे और सौहार्द के लिए प्रेम को फैलाना होगा। शिवेंद्र ने कहा कि हमें जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर बांटा जा रहा है। इसी को मिटाने के लिए हम यह यात्रा कर रहे हैं। सीमा राजोरिया ने कहा कि यह यात्रा महत्वपूर्ण है जिसमें लोगों से मिलकर उनकी संस्कृति और भाषा को हम जान रहे हैं। वहीं विनीत तिवारी ने कहा कि मनुष्य का श्रम और प्रेम एक दूसरे से घुले–मिले हैं। यह यात्रा कबीर, भगतसिंह और गांधी की विरासत और उनके विचारों को न केवल याद करने के लिए है बल्कि मनुष्यों के श्रम की गरिमा को फिर से स्थापित करने के लिए एकजुटता का एक अभियान भी है। इस सभा में विजय दलाल जी ने शैलेंद्र का गीत "किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार" गाया तथा अंकित ने अपनी शायरी भी सुनाई। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे युवा कवि अभिषेक 'अंशु' ने कहा कि आज का दौर बेहद चुनौतीपूर्ण है। नफरत चरम पर है। इस परिस्थिति का सामना हमें प्रेम और सद्भाव से करके यात्रा को सफल बनाना होगा।

इस संवाद के बाद जत्था किला कोठी गय जहां प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यात्रा के अंत में जत्थे के साथियों ने स्थानीय लोगों के हथकरघों पर जाकर उनके श्रम और कलाकारी को देखते हुए उनसे संवाद किया।

इस जत्था में भारतीय जन नाट्य संघ अशोक नगर के संस्कृतिकर्मी, इंदौर के लेखक साथी और छतरपुर के कलाकार साथी समेत स्थानीय पत्रकार और आम जन शामिल रहे। जिनमें सीमा राजोरिया, अफरोज खान, पंकज दीक्षित, विनोद शर्मा, रतनलाल पटेल, कबीर राजोरिया, अनूप शर्मा, सत्यभामा राजोरिया, कुश कुमार, नीरज कुशवाह, गिरिराज कुशवाह, अभिदीप, सर्वेश खरे, शिवेंद्र शुक्ला, अंकित, विनीत तिवारी, विजय दला, फारुख मोहम्मद, भूपेंद्र आदि की सक्रिय भूमिका रही।

डॉ. स्वामीनाथन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी किसान आयोग की सिफारिशों को लागू करना

सोमा मार्ला

एक साल पहले मैं दिल्ली से भोपाल की ट्रेन से यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान ट्रेन में अपने डिब्बे में मेरी मुलाकात कुछ किसानों के साथ हुई। मैंने अपना परिचय देते हुए बातों–बातों में उनसे पूछा कि क्या वे डॉ. स्वामीनाथन जी को जानते हैं। उनमें से दो ने तुरंत सकारात्मक अंदाज में सिर हिलाया और कहा, ''स्वामीनाथन सिफाारिशों को लागू करो''। देश भर में किसान न केवल अत्याधिक उपज वाले बौने गेहूं कल्याण सोना को जानते हैं बल्कि फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित किसान पक्षीय अनुशंसाओं के बारे में जानते हैं। यह हरित क्रांति के अग्रदूत की विरासत है जिनके अनुसंधानों से 1950 का खाद्य उत्पादन 0.5 करोड़ टन से बढ़कर 2023 में लगभग 33 करोड़ टन पहुंच गया है। मुझे स्वामीनाथन के दो प्रसिद्ध नारे याद हैं ''तुम बंदूक खरीद सकते हो लेकिन अनाज कभी नहीं'' और ''भविष्य उन देशों का है जिनकी खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता है''। यह वास्तव में एक उदास दिन है कि हमने एक देशभक्त वैज्ञानिक खो दिया जिनकी दूरदृष्टि और मिशन ने अकालों को दूर भगा दिया था और जो दूरदृष्टि और मिशन खाद्य सुरक्षा लाई।

60 और 70 के शुरुआती दशक में मेरी प्राथमिक शिक्षा के दौरान देश में खाद्यान्न की बहुत कमी होती थी। लोग राशन और किराना दुकानों में चावल और गेहूं है या नहीं की बातें करते थे। उन दिनों दुकानों में अनाज की उपलब्धता अमरीकी जहाजों के भारत के बंदरगाहों पर आगमन से होती थी जो कि अपमानजनक पीएल–480 समझौते के तहत अनाज लाते थे। वह देश के लिए मात्र तुरंत की जरूरत को पूरा करने की जैसी स्थिति थी। उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन और अन्य वैज्ञानिकों को केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से आदेश था कि खाद्य अभावों को दूर करने के लिए समाधान खोजें। उस समय डॉ. एम.एस स्वामीनाथन ने डॉ. नोर्मन बोर्लोग से संबंध स्थापित किया। डॉ. बोर्लोग मैक्सिको के इंटरनेशनल वीट सेंटर (अन्तरराष्ट्रीय गेहूं केंद्र) में एक अमरीकी वैज्ञानिक थे। डॉ. बोर्लोग ने उन दिनों ही गेहूं की लाल और बौनी अत्याधिक उपज वाली किस्म विकसित की थी। डॉ. स्वामीनाथन ने डॉ. बोर्लोग से संपर्क किया और मैक्सिकन गेहूं के कुछ बीज भारत लाए और भारत के खेतों में उनके होने की संभावनाओं का परीक्षण किया। नई दिल्ली और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में खेतों में इनका परीक्षण किया गया, परीक्षण ने भारतीय गेहूं (लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर) के मुकाबले कहीं अधिक उत्पादन दिया। इन नतीजों से हिम्मत पाकर डॉ.

स्वामीनाथन और उनकी आईएआरआई पूसा के जेनेटिक विभाग की क्रॉप ब्रीडर टीम ने मैक्सिन और भारतीय देशी गेहूं की कई संकर किस्में तैयार करने की कोशिश की। कुछ सालों के बाद कमरतोड़ संकर प्रयास और फिल्ड रिसर्च से उन्हें सोनारा 64, सेनालिका जैसी प्रसिद्ध गेहूं की किस्में प्राप्त हुई और बाद में प्रसिद्ध कल्याण सोना किस्म। कुछ ही समय में ये अत्याधिक उपज वाली किस्में पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में फैल गई। इसी तरह डॉ. स्वामीनाथन ने चावल फसल की सुधार परियोजनाओं का भी नेतृत्व किया। अधिक फसल देने वाली ताइवान की मशूरी किस्म टीएन.21 और आईआर चावल किस्मों का भारत की लंबी और कम फसल देने वाली भारत की चावल की किस्मों के साथ संकर किया गया। इन संकरों के नतीजे बेहद अच्छे रहे और अत्यधिक फसल देने वाली चावल की किस्म आईआर.8 जया और अन्य प्रसिद्ध किस्मों ने भी अत्यधिक उपज दी। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और पब्लिक सेक्टर के वैज्ञानिकों ने कुछ ही समय में अत्यधिक उपज वाली बौनी चावल की किस्म दी जो बहुत ही कम समय में जंगल की आग की तरह देश भर में फैल गई। 70 के उत्तरार्ध तक चावल और गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ गया और देश ने खाद्य आयात करना छोड़ दिया। इस खाद्य आयात पर निर्भर भूख पीड़ित देश को आत्मनिर्भर, पर्याप्त खाद्यान्न तक ले जाने की सफल कहानी का श्रेय डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की दूरदृष्टि योजना को जाता है।

2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने गंभीर कृषि संकट और बढ़ती संख्या में किसान आत्महत्याओं के खतरों को देखते हुए डॉ. स्वामीनाथन की चेयरमेनशिप में इस ग्रामीण संकट से बाहर निकलने का सुझाव देने को कहा। उनके आयोग में एक ओर वाम पक्षीय अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अतुल कुमार अनजान और महाराष्ट्र से दक्षिण पक्षीय शेतकारी संगठन के श्री जोशी शामिल थे। स्वामीनाथन खुले दिमाग के थे और उन्होंने वास्तविक रूप में उन सब मुद्दों को शामिल किया जो कि किसान के कल्याण के पक्ष में थे। एक विस्तृत अध्ययन के बाद 2008 में आयोग ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दीं। फसल समर्थन मूल्य की पुनर्गणना उसमें महत्वपूर्ण है, साथ ही उन सुधारों में से कुछ है जैसे कि पर्यावरणीय अनुकूल खेती, महिलाओं को समान वेतन और भू–स्वामित्व अधिकार और भूमि सुधार। यूपीए कार्याकाल की दोनों सरकारों में हालांकि इन सिफारिशों को स्वीकार किया लेकिन इस आयोग की अनुशंसाओं को कभी गंभीरता से लागू नहीं किया। 2014 में आई वर्तमान सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया लेकिन इस पर अमल नहीं किया। वर्तमान सरकार ने यहां तक सर्वोच्च न्यायालय में घोषणा की कि वह किसानों को फसल उत्पादन के लिए न्यायसंगत समर्थन मूल्य देने के द्वारा बाजार हितों को नुकसान पहुंचाने के पक्ष में नहीं है। तदनंतर, बेहतर फसल मूल्य की मांग के लिए किसानों का असंतोष बढ़ा और उनके प्रदर्शन के दौरान मंदसौर, मध्यप्रदेश में दुःखद रूप से छः किसान मारे गए। किसानों ने ऐतिहासिक नासिक और संसद मार्च निकाला जिसका चरमबिंदु लगभग डेढ़ साल लंबा चला दिल्ली प्रदर्शन था जिसमें एग्री बिजनेस पक्षीय तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की थी।

2011 में डॉ. स्वामीनाथन ने राज्य सभा के सदस्य की हैसियत से महिला किसानों के लिए समान भूमि अधिकार के लिए एक निजी सदस्य विधयेक प्रस्तावित किया। दुर्भाग्यवश समर्थन के अभाव में विधेयक पारित नहीं हुआ।

हरित क्रांति का एक समझौता भी था। अति घोषित हरित क्ररंति देश के लिए खाद्य आत्म निर्भरता लाई लेकिन इससे मृदा नष्ट हुई, नदियां, तालाब प्रभावित हुए और छोटे और मझोले किसानों को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। हरित क्रांति के अंतर्हित एजेंडे से फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड, मशीनरी उद्योग और ट्रेडर लॉबी मुख्यतः लाभान्वित हुई। इसके लिए यह दोष परवर्ती सरकारों को देना चाहिए जिसने अमीर किसानों के पक्ष में और बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट एग्रीबिजनेस सिंडिकेट के लिए काम किया।

डॉ. स्वामीनाथन ने कृषि की शिक्षा कोयम्बटूर एग्रीकल्चरल इन्स्ट्रीच्यूट पूसा नई दिल्ली से की। अपने डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल शोध को पूरा करने के लिए वे नीदरलैंड और इंगलैंड गए। मनुष्य निर्मित त्रासद बंगाल अकाल ने उन्हें भारत लौट कर और कृषि शोध में काम करने के लिए राजी किया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीच्यूट में लगभग चार दशकों की सेवा और बाद में इस संस्थान के निदेशक के तौर पर इन्होंने अपनी दूरदृष्टि योजना से क्रॉप ब्रीडिंग का संचालन एवं नेतृत्व किया और गेहूं, चावल, आलू और कई अन्य फसल उपजों में बहुमूल्य सुधार किया। उन्हे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था जिसमें शुरुआती सम्मान वर्ल्ड फूड प्राइज से लेकर पदमविभूषण, रमन मेगासे अवार्डएवं कई अन्य पुरस्कार मिले।

सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थपना की और जैव विविधता के लिए हर संभव प्रयास किए, समुद्र तटीय मेनग्रोव के संरक्षण, महिला धान किसानों के कल्याण के लिए काम किया। उनके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट पहलू था कि वे इतने उच्च पद पर पहुंचने क बावजूद अपने चैन्नई के आवास पर सभी छोटे किसानों से लेकर, शोध कार्य में जूझ रहे छात्रों से लेकर शीर्ष सरकारी अधिकारियों तक से मिलते थे।

डॉ. स्वामीनाथन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की पुनर्गणना करना और किसान आयोग की अनुशंसाओं पर विशिष्ट रूप से संसद में चर्चा करना ताकि किसानों और खेत मजदूरों की आजीविका में सुधार हो सके।

पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना निंदनीय

पटना, 3 अक्टूबर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने एक न्यूज पोर्टल के पत्रकारों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। हिरासत में लिए गए सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये सभी जनता के हित में सवाल उठाते रहे हैं और जनपक्षीय हैं। उर्मिलेश तो लंबे अरसे तक पटना में काम कर चुके हैं। उन्हें भी पुलिस की हिरासत में लिया गया है। ईमानदार और निडर पत्रकार के रूप में उन सबका नाम चर्चित है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि हमारी पार्टी दृढ़ता से मीडिया के साथ और भाषण और अभिव्यक्ति की संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रता के लिए खड़ी है। पिछले नौ वर्षों में भाजपा सरकार ने जनता के सवाल उठाने वाले और सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई की है। भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों द्वारा मीडिया संगठनों पर कब्जा करने की सुविधा देकर मीडिया को अपने पक्षपातपूर्ण और वैचारिक हितों के लिए मुखपत्र में बदलने की भी कोशिश की है। सरकार और उसके विचारधारा से जुड़े संगठनों ने सत्ता के सामने सच बोलने वाले व्यक्तिगत पत्रकारों के खिलाफ प्रतिशोध का सहारा लिया है। भाजपा सरकार की दमनकारी कार्रवाइयां हमेशा केवल उन मीडिया संगठनों और पत्रकारों के खिलाफ होती हैं जो सत्ता के लिए सच बोलते हैं। विडंबना यह है कि जब देश में नफरत और विभाजन को भड़काने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो भाजपा सरकार पंगु हो जाती है। राष्ट्रीय हित में भाजपा सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह राष्ट्र और लोगों की चिंता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए मीडिया पर हमला करना बंद करे।

भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है चुनावी बांड पर निर्णय में देरी

भाजपा की वित्तीय ताकत के कारण देश के चुनावों में समान अवसर नहीं

नित्य चक्रवर्ती

एक बार फिर भारत सरकार ने 4 अक्तूबर से दस दिनों तक चलने वाले चुनावी बांड की 28वीं किश्त की बिक्री को मंजूरी दे दी है और हमेशा की तरह ऐसा ठीक चुनावों के पहले किया जा रहा है जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुछ हफ्ते ही रह गये हैं। इस बार भी भाजपा को अपने चुनाव अभियान में एक और बड़ा इनाम मिलेगा क्योंकि लगभग 80 से 90 प्रतिशत धन सत्तारूढ़ पार्टी को जाता है। केंद्र शर्मनाक तरीके से मौजूदा चुनावी बांड नियमों को अन्य विपक्षी दलों की कीमत पर भाजपा के पक्ष में इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट अब भी उस याचिका पर सुनवाई में देरी कर रहा है जो लंबे समय से लंबित है।

मूल चुनावी बांड योजना 2017 को 2018 में कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। लेकिन इस साल अप्रैल में ही, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने संकेत दिया था कि वह सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ की स्थापना के बारे में फैसला करेंगे। याचिकाएँ पर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई।

चुनावी बांड की 25वीं किश्त के मामले में, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल 7 नवंबर को चुनावी बांड योजना के नियमों में जल्दबाजी में संशोधन करके औचित्य का उल्लंघन किया, ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने वाले वर्ष के दौरान अतिरिक्त पंद्रह दिनों के लिए बिक्री की अनुमति दी जा सके।

नियमों के अनुसार, बांड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध हैं। आम चुनाव के वर्षों में 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि की अनुमति है। अब नवीनतम संशोधन के माध्यम से, केंद्र ने पिछले साल हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनावों से पहले नवंबर 2022 में एक और किश्त की अनुमति दी।

जनवरी 2018 में चुनावी बांड की बिक्री शुरू होने के बाद से पिछले पांच वर्षों में, भाजपा ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश में राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किये हैं और गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदा है। महाराष्ट्र में, यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था कि जुलाई 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से एकनाथ शिंदे समूह के दलबदल को सुनिश्चित करने के लिए भारी धनराशि जुटाई गयी थी।

इसके बाद वहां शिंदे–भाजपा की सरकार बनी। विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के इन सभी कदमों में, भाजपा ने कारपोरेट दान, चुनावी बांड के पैसे के साथ–साथ विदेशी दान के माध्यम से जुटाये गये अपने विशाल उपलब्ध धन का उपयोग किया। कारपोरेट्स के चुनावी ट्रस्टों ने भी राजनीतिक दलों को धन दिया और वहां भी, भाजपा ने हाल के वर्षों में 80 प्रतिशत से अधिक धन जुटाया।

बॉन्ड या पोल ट्रस्ट से फंडिंग करना भाजपा के लिए एक रास्ता है क्योंकि जो कंपनियां दान देती हैं वे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को नाराज नहीं करना चाहती हैं और आईटी विभाग, सीबीआई या ईडी के माध्यम से कार्रवाई को आमंत्रित नहीं करना चाहती हैं। यह तब स्पष्ट हुआ जब बजाज परिवार के वंशज राजीव बजाज पिछले साल राहुल गांधी के साथ बातचीत के बाद केंद्रीय एजेंसियों द्वारा संभावित प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के प्रति आशंकित थे।

भारतीय कारपोरेट्स के बीच यह डर इतना जबरदस्त है कि औद्योगिक घरानों के युवा वंशज, जो दूरदर्शी हैं और भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, चुप रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ कुछ उदारवादियों के लिए अपनी कंपनियों के भविष्य को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हैं। कुल मिलाकर नतीजा यह है कि चुनावों में बराबरी का कोई मौका नहीं है। विपक्षी दलों की तुलना में भाजपा दस गुना से भी ज्यादा पैसा खर्च करने की स्थिति में है। जरूरत पड़ने पर दल–बदल कराने के लिए इसके पास एक विशाल युद्ध संदूक है। नरेंद्र मोदी शासन के पिछले नौ वर्षों में, भारतीय कार्पोरेट क्षेत्र में धन का असामान्य संकेंद्रण हुआ है। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारत की बीस सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों ने 1990 में कुल कॉर्पोरेट मुनाफे का 14 प्रतिशत, 2010 में 30 प्रतिशत और 2019 में 70 प्रतिशत अर्जित किया।

इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी के शासन के पहले पांच वर्षों के दौरान कुछ कारपोरेट घरानों में धन के संकेंद्रण में भारी उछाल आया। पिछले चार वर्षों में यह प्रक्रिया और तेज हुई है। यह सत्तारूढ़ दल भाजपा और बड़े उद्योगपतियों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग का परिणाम है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान शासन के दौरान लाभ हुआ है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटकों को भारतीय धनी पूंजीपतियों और नरेंद्र मोदी शासन के बीच इस बदले की भावना पर ध्यान केंद्रित करना होगा और इस बात की जांच की मांग करनी होगी कि कैसे बड़े कारपोरेट अपनी दीर्घकालिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को वित्त पोषित कर रहे हैं।

उनके कानूनी विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की शीघ्र सुनवाई पर जोर देना चाहिए ताकि विद्वान न्यायाधीश कम से कम अंतिम निपटान तक चुनावी बांड योजना पर रोक लगाने का आदेश दे सकें। चुनाव लड़ने वाले दलों के बीच समान अवसर स्थापित करके देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए यह जरूरी है। (संवाद)

दो नवम्बर की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली ऐतिहासिक होगी: भाकपा

राज्य परिषद की बैठक में रैली की तैयारी को लेकर बनाई गई रणनीति

पटना, 08 अक्टूबर 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद की बैठक रविवार को जनशक्ति भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अवधेश कुमार राय और मसऊद मंजर की अध्यक्षमंडली ने की। बैठक को राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय, राज्य सचिव मंडल सदस्य विजय नारायण मिश्र, अजय कुमार सिंह, प्रमोद प्रभाकर, मिथिलेश कुमार झा आदि ने संबोधित किया। राज्य सचिव मंडल सदस्य जब्बार आलम ने पार्टी कोष पूरा करने वाले जिला सचिवों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बैठक में राज्य के सभी 38 जिलों के जिला सचिव एवं राज्य परिषद के सदस्य मौजूद थे।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि पार्टी की दो नवम्बर को गांधी मैदान में आयोजित भाजपा हटाओ, देश बचाओ रैली ऐतिहासिक होगी। आज देश के सामने अनेक गंभीर चुनौतियाँ हैं। भाजपा के नेतृत्ववाली केन्द्र सरकार की दक्षिणपंथी फासीवादी रूझान वाली विचारधारा और कारपोरेटपक्षी नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण देश की जनता अभूतपूर्व संकट झेल रही है। गंभीर आर्थिक संकटों, मसलन बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता, खाद्य संकट, गरीबी, कुपोषण से किसान–मजदूर–मध्यवर्ग और दूसरे गरीब तबके के लोग इससे निजात पाने के लिए अकूला रहे हैं। इतना ही नहीं संविधान के आदर्शों और मूल्यों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघीय ढाँचा, सामाजिक न्याय पर केन्द्र सरकार की ओर से निर्ममता पूर्वक प्रहार हो रहा है। इन सब का मूल कारण भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार है। सरकार की इन नीतियों और कुकृत्यों का विरोध भी लोग नहीं कर पा रहे है क्योंकि यह सरकार आम लोगों की आवाज दबा रही है। अब देश के सामने एक ही रास्ता है 2024 में सत्ता से भाजपा को हटाना। इसी दिशा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यभर में 'भाजपा हटाओ देश बचाओ' नारे के साथ व्यापक पदयात्रा और जनसत्याग्रह कार्यक्रम चलाया। अगली कड़ी में दो नवम्बर को पटना के गांधी मैदान में रैली आयोजित की जा रही है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए देश की दो दर्जन से अधिक राजनीतिक पाटियाँ एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल है। अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केन्द्र की आततायी, जनविरोधी, संविधान विरोधी नरेन्द्र मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रैली की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जानकी पासवान ने कहा कि भारतीय खेत मजदूर यूनियन का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन दो से पांच नवम्बर तक पटना में आयोजित होना है। इसकी तैयारी गांव गांव शुरू कर दी जाये।

ईरान की बहादुर महिला नर्गिस मोहम्मदी को सलाम

एल एस हरदेनिया

नर्गिस मोहम्मदी को इस वर्ष के नोबल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान ईरान में महिलाओं के शोषण के विरूद्ध और उनके मानवाधिकारों के लिए सतत संघर्ष के लिए दिया जा रहा है। यहां यह स्मरणीय है कि ईरान में महिलाओं का एक सशक्त आंदोलन तब प्रारंभ हुआ जब वहां की एक 22 वर्षीय युवती की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इस महिला को ईरान की तथाकथित धार्मिक पुलिस गाईडेंस पेट्रोल द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

इस घटना के बाद ईरान की महिलाओं ने एक शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को कुचलने के प्रयास में बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 44 नाबालिग भी थे। बीस हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए।

पुरस्कार की घोषणा करते हुए इस बात का उल्लेख किया गया कि ईरान की धार्मिक सरकार द्वारा किस तरह देश में ऐसे लोगों के विरूद्ध भारी दमन चक्र चलाया जा रहा है जो सरकार की दमनकारी नीतियों के विरूद्ध सतत अभियान चला रहे थे। इस संघर्ष में नर्गिस ने पूरी हिम्मत के साथ भाग लिया था।

51 वर्षीय नर्गिस उन 137 व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें शांति स्थापित करने और शोषण के विरूद्ध संघर्ष के लिए यह उच्चतम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार सन् 1901 में स्थापित किया गया था। अब तक यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा सहित कई महान हस्तियों को प्रदान किया जा चुका है। नर्गिस शांति पुरसकार पाने वाली 19वीं महिला हैं और ईरान की दूसरी। ईरान की जिस दूसरी महिला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया उनका नाम शीरीन एबादी हैं जिन्हें सन् 2003 में यह पुरस्कार मिला था।

मोहम्मदी कई वर्षो से महिलाओं पर होने वाली ज्यादतियों के विरूद्ध संघर्षरत हैं। वे इस समय 10 साल की सजा भुगत रही हैं। उन्हें ईरान की सरकार के विरूद्ध लगातार प्रचार करने के आरोप में सजा दी गई है। उनके तीन दशक लंबे संघर्ष के कारण ईरान में शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के हित के कई सुधार हुए हैं। लेकिन इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उन्हें अपनी आजादी, इंजीनियरिंग का अपना प्रोफेशन और अपना परिवार–बहुत कुछ खोना पड़ा है। उनके पति, जो उनके संघर्ष में उनके सहयोगी रहे, और उनकी जो जुड़वां बेटियों को उनकी विचारधारा के चलते फ्रांस में निर्वासित जीवन बिताना पड़ रहा है। वे पिछले आठ वर्षो से अपने परिवार से नहीं मिलीं हैं।

उनके बेटे अली रहमानी कहते हैं कि उन्हें अपनी मां पर गर्व है। यह पुरस्कार सिर्फ मां के त्याग और बहादुरी का सम्मान नहीं है बल्कि यह पूरे ईरान की महिलाओं का सम्मान है।

मोहम्मदी अब तक 13 बार गिरफ्तार की जा चुकी हैं और पांच बार सजा भुगत चुकी हैं। उन्हें कुल मिलाकर अब तक 31 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उन्हें 154 कोड़ों की सजा भी दी गई है। जेल में रहते हुए भी वे ईरान और दुनिया की समस्याओं पर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करती रहती हैं। वे जेल से ही कई अभियान चलाती रहतीं हैं।

नोबल पुरस्कार मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मान मुझमें और जोश भरेगा भले ही मुझे पूरा जीवन जेल के सींखचों के पीछे बिताना पड़े। मैं ताजिंदगी लोकतांत्रिक अधिकारों, आजादी और समानता के लिए लड़ती रहूंगी। यह पुरस्कार मुझे और ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ और आशावादी बनाएगा। मेरे संघर्ष को दी गई यह मान्यता ईरान के नागरिकों के बदलाव के लिए जारी संघर्ष को और तीव्र, मजबूत और संगठित बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अंततः हमारी जीत होगी।

मार्च जिसने जनता को जागृत किया

आर अजयन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के आह्वान पर ''भाजपा हटाओ, देश बचाओ'' अभियान केरल में सफलतापूर्वक चलाया गया। केरल में पार्टी की सभी स्थानीय समितियों द्वारा 1 से 30 सितंबर तक मार्च आयोजित किए गए। ''भाजपा हटाओ, देश बचाओ'' का यह अभियान मार्च 2024 के आम चुनावों के लिए आगामी अभियान की एक पूर्व भूमिका बन गया। मार्च का नेतृत्व जमीनी स्तर पर कैडरों द्वारा किया गया था, इसलिए आम लोगों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित की गई। पूरे मार्च के दौरान वक्ताओं द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। उन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के नेतृत्व वाली केरल राज्य सरकार और उसकी नीतियां भाजपा सरकार का राजनीतिक विकल्प हैं। प्रचारकों के लिए राजनीतिक दस्तावेज और पर्चे सीपीआई राज्य परिषद द्वारा जिला समितियों के माध्यम से वितरित किए गए थे। यह अभियान बेहद अनोखे तरीके से किया गया। स्थानीय समिति सचिवों को मार्च के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। राज्य परिषद ने निर्देश दिया था कि यह अनिवार्य होगा कि मार्च की उप–कप्तान महिलाएं और जन संगठनों के नेता हों। इससे मार्च में महिला कार्यकर्ताओं की अच्छी भागीदारी सुनिश्चित हुई।

किसी पार्टी के कामकाज के लिए स्थानीय और शाखा स्तर पर कार्यकर्ता अपरिहार्य हैं। ये कैडर बातचीत करते हैं और आम लोगों के मामलों में शामिल होते हैं। लोगों की नजर में शाखा और स्थानीय स्तर पर कैडर अपने इलाके के नेता होते हैं। इसलिए, पार्टी ने निर्णय लिया था कि शीर्ष समितियां मार्च को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी लेकिन स्थानीय समिति के सचिव और अन्य स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता मार्च का संचालन करेंगे। अभियान का दोहरा लक्ष्य था। एक था नरेंद्र मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों और कार्यो को उजागर करना। दूसरा था आम लोगों के बीच पार्टी के प्रभाव को फिर से बढ़ाना। हमने इन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। स्थानीय मार्चो ने, जिनमें महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, लोगों को आकर्षित किया। सीपीआई केरल राज्य परिषद द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियान में 90: निदेशक और उप कप्तान महिलाएं थीं। इन मार्चो से पार्टी इकाइयों का कायाकल्प हो गया।

केरल में 941 पंचायतें और 87 नगर पालिकाएँ हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की कुल संख्या 1028 है। लेकिन हम लगभग 1300 स्थानीय मार्च आयोजित करने में सक्षम थे जबकि हमारे पास 1265 स्थानीय समितियाँ हैं। इसका मतलब यह है कि अभियान का असर जनता के बीच काफी अच्छी तरह से पहुंचा है। कार्यकर्ता इस स्तर तक सक्रिय हो गए कि कई स्थानीय समितियों के तहत दो मार्च आयोजित किए गए। सीपीआई राज्य परिषद का विचार है कि पार्टी इकाइयों द्वारा प्राप्त गति का उपयोग आगामी आम चुनाव अभियानों के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। 2024 के आम चुनावों के महत्व के कारण सीपीआई लोगों को भाजपा को हराने के लिए तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक अभियान चलाने की योजना बना रही है।

एहतिजाज की बुलंद आवाज नरगिस मोहम्मदी को नोबेल अमन इनाम

जाहिद खान

एहतिजाज की आवाज बुलंद करने वाली ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को साल 2023 के लिए नोबेल अमन इनाम से नवाजे जाने का ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है, जब दुनिया के कई बड़े मुल्कों में दक्षिणपंथी ताकतें सत्ता में हैं और अपने खिलाफ असहमति की जरा सी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। आलम यह है कि सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हाशिए पर हैं। यहां तक कि मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वालों दोनों को वहां शक की निगाह से देखा जा रहा है। उन्हें जन विरोधी कानूनों के तहत जेल भेजा जा रहा है। उन पर अत्याचार हो रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतकर, नरगिस मोहम्मदी दुनिया की उन उन्नीस महिलाओं में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार को अपने नाम किया है। ईरान ही की शिरीन एबादी, भारत–मदर टेरेसा, पाकिस्तान–मलाला यूसुफजई और फिलीपींस की मारिया रेसा वे कुछ अहम महिलाएं हैं, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार से अभी तलक सम्मानित किया जा चुका है।

नोबेल पुरस्कार के 122 साल के इतिहास में यह पांचवीं बार है, जब शांति पुरस्कार किसी ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो जेल में है या फिर घर में नजरबंद है। नार्वे नोबेल समिति ने इस पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा है कि ''नरगिस मोहम्मदी को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार देकर, नार्वे नोबेल समिति ईरान में मानवाधिकारों, आजादी और लोकतंत्र के लिए उनकी हिम्मती लड़ाई का सम्मान करना चाहती है।'' समिति ने अपने बयान में आगे कहा, ''इस साल का शांति पुरस्कार उन लाखों लोगों को भी सम्मानित करता है, जो पिछले कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न की धार्मिक नीतियों के खिलाफ विरोध करते रहे हैं। नरगिस मोहम्मदी ने लगातार भेदभाव और उत्पीड़न का विरोध किया है। उन्होंने सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के लिए संघर्ष की वकालत की है।'' नोबेल समिति का कहना था कि, ''नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को तेरह बार गिरफ्तार किया गया, पांच बार गुनहगार ठहराया गया और कुल 31 साल जेल और 154 कोड़े की सजा सुनाई गई। उसे अपने इस जाँबाजी भरे जद्दोजहद के लिए व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी।''

गौरतलब है कि साल 1901 में स्थापना के बाद से नोबेल शांति पुरस्कार अभी तलक 110 व्यक्तियों और 30 संगठनों को दिया गया है। इस साल 350 से ज्यादा लोग इस पुरस्कार की दौड़ में थे। पुरस्कार के दावेदारों में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल थे। जबकि पिछले साल यह पुरस्कार, रूस के यूक्रेन पर चल रहे आक्रमण की पृष्ठभूमि पर शांति को बढ़ावा देने के वास्ते रूसी मानवाधिकार समूह मेमोरियल, यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और जेल में बंद बेलारूसी अधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। बहरहाल, इस साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर नार्वे की राजधानी ओस्लो में नरगिस मोहम्मदी को एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी तकरीबन 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

पिछले साल ही अपनी जिंदगी के पचास साल मुकम्मल करने वाली नरगिस मोहम्मदी, ईरान की अव्वल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जो बरसों से महिला अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह बतलाना लाजिमी होगा कि ईरान, मानवाधिकार अधिकारों और उनमें भी महिलाओं के अधिकारों के मामले में सबसे बुरे मुल्कों में से एक है। यहां जो भी इन अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, उनका जबर्दस्त दमन किया जाता है। उन पर अत्याचार और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। नरगिस मोहम्मदी ने 1990 के दशक से जब वे महज बीस साल की थीं, अपने मुल्क में समानता और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना शुरू की। वे एक अच्छी राइटर भी हैं। अपने ख्यालात को अवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अखबारों के लिए आर्टिकल लिखे। नरगिस की एक किताब 'व्हाइट टॉर्चरः इंटरव्यूज विद ईरानी वूमेन प्रिजनर्स' भी प्रकाशित हो, चर्चा में रह चुकी है। इस किताब ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और मानवाधिकार फोरम में 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' के लिए एक पुरस्कार भी जीता है।

शिरीन एबादी के नेतृत्व वाले एक गैर–सरकारी संगठन, 'डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर' की उप प्रमुख नरगिस मोहम्मदी ने हमेशा समानता और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्हें 2011 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उन पर जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की मदद करने का इल्जाम था। इस 'गुनाह' के लिए उन्होंने कई सालों तक जेल की सजा काटी। बहरहाल, मोहम्मदी दो साल बाद जमानत पर रिहा हुई। इसके बाद भी उन्होंने अपनी ये लड़ाई जारी रखी। जेल का अकेलापन एवं यातनाएं भी उनका हौसला और इरादा तोड़ नहीं पाई। कुछ अरसे बाद नरगिस मोहम्मदी, सजा–ए–मौत के खिलाफ चलाई गई एक मुहिम में शामिल हुई। इसके लिए साल 2015 में उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और उनकी सजा को बढ़ा दिया गया। वो तब से ही जेल में बंद हैं। नरगिस मोहम्मदी, जेल में भी खामोश नहीं बैठ गई। जेल से ही उन्होंने सियासी कैदियों पर सत्ता के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार अपना विरोध जताया है। उनके अधिकारों की हिफाजत की पैरवी की है। खास तौर पर महिला कैदियों पर हो रहे उत्पीड़न और यौन हिंसा के मामले में वे ज्यादा मुखर हैं और लगातार इसकी मुखालफत कर रही हैं।

सितंबर, 2022 में एक युवा कुर्दिश महिला महसा जीना अमिनी ईरान की मोरेलिटी पुलिस की हिरासत में मारी गई। इस वाकिआत के बाद, लोगों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। देशभर में महिलाओं के अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया थी। 'औरत–जिंदगी–आजादी' के नारे के तहत हजारों ईरानियों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 1979 में सत्ता में आने के बाद से ईरान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ यह सबसे बड़े राजनीतिक प्रदर्शन थे। सरकार, इन प्रदर्शनों से घबरा गई और इस विरोध को कुचलने के लिए उसने कड़ी कार्रवाई की। जिसमें 500 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। हजारों लोग घायल हुए। कई लोग पुलिस की चलाई रबर की गोलियों से अंधे हो गए। इस दरमियान तकरीबन 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नरगिस मोहम्मदी ने तेहरान की एविन जेल में बंद रहते हुए, इस प्रदर्शन की पुरजोर हिमायत की। उन्होंने जेल में ही अपने साथियों को इकट्ठा कर, देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के साथ अपना समर्थन दर्ज कराया। जेल की सख्त हालात में भी वह बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने में कामयाब रहीं। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के साथ–साथ उन्हें बेदार किया। जाहिर है कि इस पर जेल अफसरों ने बौखला कर नरगिस पर और भी कड़ी पाबंदियां लगा दीं। उन्हें किसी से फोन पर बात करने या किसी से मिलने से भी पाबंद कर दिया। बावजूद इसके उन्होंने किसी तरह 'न्यूयॉर्क टाइम्स' को अपना एक लेख भेजा। अखबार ने इसे महसा अमिनी की हत्या की पहली सालगिरह पर छापा। मोहम्मदी ने इस लेख में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, ''वे हममें से जितने ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करेंगे, हम उतना मजबूत होंगे।''

नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान के बाद, दुनियाभर के अमनपसंद, इंसानियत के हिमायती और मानव अधिकारों के समर्थकों ने इस फैसले की जहां खुलकर तारीफ और अपनी खुशी जताई है, तो दूसरी तरफ ईरान सरकार ने इसकी निंदा करते हुए, इस कदम को 'पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक' बताया है। जाहिर है कि यह नकारात्मक बयान, मौजूदा ईरान हुकूमत की हताशा और निराशा को दिखलाता है। वह नरगिस मोहम्मदी को मिले इस पुरस्कार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्योंकि जब पुरस्कार की बात होगी, तो ईरान के राजनीतिक और सामाजिक माहौल का भी जिक्र होगा। वहां मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ क्या गलत सुलूक हो रहा है?, जेर ए बहस होगा। आजादी का ख्याल और अपने हुकूकों के जानिब जब एक बार किसी कौम में बेदारी आ जाती है, तो उस ख्याल को कोई ताकत नहीं रोक पाती। ईरान सरकार को चाहिए कि वह नरगिस मोहम्मदी को मिले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का न सिर्फ खैर–मक्दम करे, बल्कि नरगिस समेत सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ईरानी जेलों से फौरन रिहा किया जाए। अपनी आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित कर, कोई भी सरकार अपने आप को सभ्य होने का दावा नहीं कर सकती। फिर बात, स्वतंत्रता और समानता की भी है। जो नागरिकों के बुनियादी अधिकार हैं।

'भाजपा हाराओ, इंडिया जिताओ' का आह्वान

पेज 1 से जारी...

जाती है, कभी पाकिस्तान आ जाता है, कभी चीन आ जाता है, कभी भारत खड़ा कर देते हैं और अब सनातन ले आए । उन्होंने कहा जनता को इससे बचाना है और सरकार को अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों और सवालों को लेकर निरंतर घेरे रखना है। यह जो उसका विरोध करते हैं उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं चाहे ईडी चाहे सीबीआई–वगैरा हो। यह सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि जनता का हित ना हो सके और रईसों का हित हो सरकार का धार्मिक विग्रह पैदा करना एक प्रमुख मुद्दा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके कार्यकर्ता 2024 के चुनाव में इनको अवश्य हराएंगे और उनकी साजिशों को फेल करेंगे।

इस अवसर पर भाकपा (मा) महामंत्री सीताराम येचूरी ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत और हिंसा की राजनीति की जा रही है और इस चीज को उत्तर प्रदेश की और समूचे देश की जनता देख रही है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को बदलना चाहती है देश के संविधान को लोकतंत्र को आर्थिक नीतियों को देश की धर्मनिरपेक्षता को सबको बदलना चाहती है और काम के और रोजगार के अवसर और शिक्षा के अवसर को तथा सामाजिक न्याय के अवसर को छीन लेना चाहती है।

उत्तर प्रदेश की जनता को इससे मुकाबला करना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है।

भाकपा (मा) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल पारित करवाया गया परंतु ना तो उसमें रिजर्वेशन दिया गया और ना ही वह सन 2024 से लागू होगा एक तरह से लोगों को भुलावे लावे में रखा गया।

उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की की 2024 में उनको बड़ी भूमिका का निर्वाह करना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है।

ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक के महामंत्री श्री जी देवराजन ने कहां रैली समय की पुकार है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है क्योंकि उसने जनता को हर तरह से लूटा है।

लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री जावेद रजा ने कहा की जनवादी शक्तियां आज की रैली के जो उद्देश्य हैं उनके साथ खड़ी है और यह अब मौका आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक दिया जाए और देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करते हुए देश की जनता के हितों की रक्षा की जाए जाए।

सभा को भाकपा (मा) पोलिट ब्यूरो की सदस्य श्रीमती सुभाषनी अली, प्रादेशिक राज्य सचिव डॉ. हीरालाल यादव, भाकपा (मोल) के वरिष्ठ नेता ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा, कृष्ण अधिकारी तथा लोकतांत्रिक जनता दल के प्रादेशिक अध्यक्ष श्री जुबेर अहमद कुरेशी तथा ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक के उत्तर प्रदेश के महामंत्री उदयनाथ सिंह ने भी संबोधित किया।

रैली अत्यंत उल्लास के वातावरण में संपन्न हुई और लोगों ने संकल्प लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा और इंडिया गठबंधन तथा वामपंथ के लोगों को जिताया जाएगा।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दरः

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रूपये

खाता नामः **मुक्ति संघर्ष वीकली**
बैंकः **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्याः **1033004704**
आईएफसी कोडः **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखें:
व्यवस्थापकः मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोटः डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष विकली'' के नाम होना चाहिए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा इंडिया

पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकालकर आक्रोश मार्च

रांचीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में इंडिया के बैनर तले घटक दलों की बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुस्ताक अंसारी, कांग्रेस के राकेश किरण, भाकपा के अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक उपस्थित थे।

पाठक ने कहा कि केंद्र की सरकार इंडिया घटक दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रही है। ताकि इंडिया गठबंधन में टूट पैदा हो सके। पाठक ने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है। तब से केंद्र की मोदी सरकार की नींद हराम हो चुकी है। अब देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। तभी तो न्यूज क्लिक सहित दिल्ली के कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल लैपटॉप को जब्त किया गया यानी केंद्र सरकार के विरोध में चाहे विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व हो या मीडियाकर्मी भाजपा के विरोध में बोलेंगे लिखेंगे खड़े होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अघोषित आपातकाल की स्थिति दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुस्ताक अंसारी ने कहा कि विपक्ष के लोगों में चाहे वो पंजाब हो बिहार या बंगाल दिल्ली या झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी विपक्षी दलों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मोदी की सरकार नहीं छोड़ रही है। इसके विरोध में लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस के नेता राकेश किरण ने कहा कि देश में नफरत की दुकान चलाने वाली केंद्र सरकार को मोहब्बत पसंद नहीं है। इसीलिए इंडिया घटक दलों से उसकी काफी नाराजगी है। इंडिया घटक दलों के तोड़ने के लिए हर हथकंडे को अपना रही है। राष्ट्रीय जनता दल के धर्मेंद्र महतो, आम आदमी पार्टी के, संतोष कुमार ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में पत्रकारों पर हमले, विपक्षी नेताओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किये जाएंगे।

भाकपा के अजय कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में इंडिया गठबंधन लगातार लड़ाई लड़ेगी। हर एक मुद्दे को लेकर सड़कों उतरा जाएगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी। शोषण जूर्म और अन्याय के खिलाफ और 2024 में केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन कटिबद्ध है। सीपीआई (एम) के अमल पांडेय, वीरेंद्र कुमार, मासस के सुशांत मुखर्जी सहित विभिन्न घटक दलों के कई नेताओं ने अपने–अपने विचार रखें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पत्रकारों एवं विपक्षी नेताओं के उपर लगातार केंद्र सरकार के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और हमलों के विरोध में 9 अक्टूबर 2023 को राजभवन मार्च कर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सोपा जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक, जिला सचिव अजय कुमार सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुस्ताक अंसारी, कांग्रेस के राकेश किरण, राष्ट्रीय जनता दल के धर्मेंद्र महतो, आम आदमी पार्टी के संतोष कुमार रजक, कांग्रेस के जोगेंद्र सिंह बेनी, भाकपा के इम्तियाज खान, त्रृणमूल कांग्रेस के जयप्रकाश साहू, अशोक कुमार वर्मा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद थे।

बलराज साहनी: जनवादी कलाकार और अग्रणी ...

पेज 5 से जारी...

को कान्स फिल्म फेस्टिवल में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वह सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय हो गये।

पीएचक्यू में काम

पीसी जोशी ने उन्हें पीएचक्यू कामरेडों की बैठकों में रिपोर्टिंग के लिए आमंत्रित किया, जिन्हें कभी–कभी डॉ. अधिकारी, बीटीआर, अजय घोष आदि ने भी संबोधित किया था। पीएचक्यू से, बलराज जीकेयू कार्यालय में बैठकों आदि के लिए मोटरसाइकिल पर पीसीजे को ले जाते थे। बलराज, प्रेम धवन, अन्ना भाऊ, अमर शेख और अन्य लोगों के साथ कहानियाँ, किट आदि तैयार करने और अपनी मोटरसाइकिल में शहर के चारों ओर घूमने के लिए काम किया।

पीसीजे ने भीष्म साहनी की बेटी का नाम कल्पना जोशी के नाम पर 'कल्पना' रखा। वह उनके परिवार के लिए 'पीसीजी' थे। बलराज ने पीसीजे के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन इस प्रकार कियाः (पीसीजे) गर्मजोशी और मित्रता ने किसी के दिल को छू लिया... राजभवन में ही मेरी पहली मुलाकात पीसी जोशी से हुई थी, और जल्द ही हमारी जान–पहचान एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गई जो यह आज तक कायम है।

'मैं आश्चर्यचकित रह गया...मैंने अपने सामने एक लापरवाही से कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखा... निश्चित रूप से, मैंने खुद से कहा, यह पीसी जोशी नहीं हो सकता.... लेकिन जब उसने प्यार भरी झलक के साथ मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा उसकी आँखों में और उसके होठों पर एक उज्ज्वल मुस्कान, मेरा संदेह दूर हो गया'।

'धरती के लाल'

1946 में निर्मित यह फिल्म सांस्कृतिक आंदोलन में एक प्रमुख मील का पत्थर थी, जिसे इप्टा ने निर्मित किया था और के ए अब्बास द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इसके कलाकारों में शोंभू मित्रा, तृप्ति से लेकर भादुड़ी, दमयंती साहनी, बलराज साहनी, अनवर मिर्जा, हामिद बट और जोहरा सहगल शामिल थे। रविशंकर संगीतकार थे। कठिन परिस्थितियों में इप्टा को लाइसेंस मिला। यह श्री साउंड स्टूडियो में शूट किए गए महान बंगाल अकाल पर आधारित था। के ए अब्बास का दो कमरों का फ्लैट प्रतिभागियों से खचाखच भर गया।

कम्युनिस्ट पार्टी, ट्रेड यूनियनों और अन्य लोगों ने अकाल आदि के लिए शहर और गाँवों से बड़ी संख्या में लोगों को संगठित किया। इप्टा की टीम भी गाँवों में काम करने गई।

यह फिल्म इस बात का उदाहरण थी कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी जन चेतना जगाने के लिए सिनेमा के माध्यम का उपयोग कर सकती है।

अपनी एक फिल्म 'हलचल' के लिए बलराज ने वास्तव में खुद को गिरफ्तार करवा लिया और जेल में रहे। दिन में उन्हें शूटिंग के लिए छोड़ दिया जाता था और शाम को जेल में वापस आ जाते थे। फिल्म में जेलर का रोल था। धरती के लाल में तो उन्होंने कई दिनों तक रिक्शा चलाने की प्रैक्टिस की थी।

फिल्म 'हकीकत' में बलराज ने 'मेजर रणजीत सिंह' का इतना प्रभावी किरदार निभाया कि उन्हें लंबे समय तक इसके लिए याद किया जाता रहा। सालों बाद उन्हें सेना के एक जवान ओम प्रकाश की याद आई जो व्हील चेयर पर बैठकर अपने 'मेजर रणजीत सिंह' से मिलने आए थे और जिन्होंने यह फिल्म कई बार देखी थी। 1962 में चीनी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध में उन्होंने अपने पैर खो दिये थे।

बीटीआर काल

दिसंबर 1947 के अंत तक पीसीजे ने सीसी में बहुमत खो दिया और 1948 में आयोजित दूसरी पार्टी कांग्रेस में उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह बीटीआर को महासचिव बनाया गया। 1947 में ही, आने वाली चीजों के संकेत दिखने लगे थे। इप्टा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को समय और धन की बर्बादी के रूप में देखा जा रहा था। इप्टा समूह विघटित होने लगे।

दीक्षांत समारोह

बलराज और दमयंती पक्के जोशीवादी थे लेकिन पार्टी अनुशासन का पालन करते थे। बीटीआर लाइन की स्थापना के बाद इप्टा लड़खड़ाने लगा। के ए अब्बास और कई अन्य लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी। संस्कृति को अब बुर्जुआ प्रवृत्ति माना जाने लगा! बलराज ने नेहरू को चिढ़ाने के लिए 'जादू की कुर्सी' लिखी और उसका मंचन किया, जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ और उन्होंने पांडुलिपि को जला दिया।

उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने तक जेल में। रिहाई के बाद, उसके दोस्त और परिचित उससे दूर रहने लगे, पार्टी के कई लोगों ने नहीं की मदद पुलिस का खतरा हमेशा बना रहता था। उन्हें अपना कार्यभार पूरा नहीं करने दिया गया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी लेकिन पार्टी में बने रहे। उन्होंने जन मोर्चो और पार्टी गतिविधियों में काम करना जारी रखा। वह बॉम्बे आईपीटीए के महासचिव बने।

एआईवाईएफ अध्यक्ष के रूप में

ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का स्थापना सम्मेलन 28 अप्रैल से 3 मई 1959 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। बलराज साहनी ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। पीके वासुदेवन नायर को कार्यकारी अध्यक्ष और डॉ. शारदा मित्रा को महासचिव चुना गया। बाद में कांग्रेस में विभाजन के बाद बलराज उसमें शामिल हो गये। लेकिन वह वहां सहज नहीं थे।

जे.एन.यू. दीक्षांत समारोह

नवंबर 1972 में जेएनयू ने उन्हें अपने दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। सीपीएम से जुड़े एसएफआई छात्रों ने इस आधार पर विरोध किया कि एक 'फिल्म स्टार' दीक्षांत समारोह को संबोधित नहीं कर सकता! लेकिन प्रशासन आगे बढ़ा और पीसी जोशी ने बलराज को परेशान न होने को कहा। जब उन्हें मंच पर लाया गया तो तनाव था। लेकिन उनके संबोधन के अंत में खड़े होकर उनका अभिनंदन किया गया और लगातार तालियां बजती रहीं।

वह कई कारणों से बहुत परेशान थे, जिनमें से एक थी उनकी बेटी शबनम की मौत। वह सांस्कृतिक और अन्य आंदोलनों की स्थिति को लेकर चिंतित थे। इन समस्याओं पर वह पीसी जोशी से चर्चा करते थे।

1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें सोवियत लैंड अवॉर्ड भी मिला।

13 अप्रैल 1973 को बलराज साहनी का निधन हो गया।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 15 – 21 अक्टूबर, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/1970) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 13.10.2023

तेलंगाना राज्य में आंगनवाडी वर्करों एवं हैल्परों की 24 दिन की हड़ताल

तेलंगाना राज्य में आंगनवाडी वर्करों एवं हैल्परों की 24 दिन की हड़ताल 11 अक्तूबर को सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। हड़ताल का नेतृत्व एटक एवं सीटू की संयुक्त कार्रवाई समिति ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चाडा वेंकट रेड्डी की पहल पर संबंधित राज्यमंत्रियों, अधिकारियों और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच समझौता वार्ता हुई। वार्ता में निम्न उलब्धियां प्राप्त हुईः

1. रिटायरमेंट के बाद वर्करों एवं हैल्परों को क्रमशः 2 लाख रु. और 1 लाख रु. का रिटायरमेंट लाभ मिलेगा। इसके लिए पहले सरकार का प्रस्ताव क्रमशः 2 लाख रु. और 1 लाख रु. के लिए था।

2. सभी को 2 लाख रु. का बीमा लाभ मिलेगा।

3. 2016 की वर्तमान वृद्ध अवस्था पेंशन आंगनवाड़ी वर्करों और हैल्परों की भी मिलेगी। पहले यह आम लोगों पर ही लागू होती थी।

4. राज्य सरकार कर्मचारियों को मिलने वाला पीआरएसी आंगनवाड़ी वर्करों पर लागू होगा। पहले, यानी तीन वर्ष पहले 30 प्रतिशत पीआरसी दिया गया था। अतः वर्करों का वेतन 10,500 रु. से बढ़कर 13,650 रु. हो गया।

5. पांच प्रतिशत की अंतरिम राहत पर भी सहमति बनी।

6. हम मांग कर रहे थे कि वेतन को 13,650 रु. से बढ़ाकर 15,000 रु. किया जाए। वह वेतन बढ़ाने पर सहमत हुए। वह वेतन में एक हजार रु. की वृद्धि कर सकते हैं।

7. वह हड़ताल की अवधि के लिए वेतन देने पर सहमत हुए।

ये हमारी प्रमुख मांगें थी। अन्य मांगों पर कुछ समय बाद विचार किया जाएगा।

संयुक्त कार्रवाई समिति ने ''हैदराबाद चलो'' का आह्वान किया था। दमन के बावजूद 5 हजार वर्कर और हैल्पर हैदराबाद पहुंचे। यह अवसर जीत के उत्सव की मीटिंग में बदल गया। मीटिंग को सीटू और एटक से संबद्ध आंगनवाडी वर्कर और हैल्पर यूनियनों के राज्य महासचिवों–जयलक्ष्मी एव नंदूरी करूणा कुमारी, विजयलक्ष्मी (एटक), मोहम्मद यूसुफ (एटक) और पी. भास्कर (सीटू) आदि ने संबोधित किया। मीटिंग में राज्य एटक सचिवगण–टी. समैया,पल्ला देवेन्द्र रेड्डी, एन. प्रसाद, आंगनवाड़ी एसोसिएशन की अध्यक्ष साई ईश्वरी एवं कोषाध्यक्ष प्यारी जान, जया, सावित्री, ज्योति, रंगलक्ष्मी एवं उपेन्द्र आदि उपस्थित थे।

डॉ. बी.वी. विजयलक्ष्मी

संयुक्त कार्रवाई समिति ने चाडा वेंकट रेड्डी, वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री टी. हरीश राव, महिला वं बाल कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़, एटक राष्ट्रीय नेता डॉ. बी.वी. विजयलक्षी, राज्य एटक अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ और भाकपा (मा) राज्य सचिवमंडल सदस्य एस. वीरैया को धन्यवाद किया है। क्योंकि चुनाव की घोषणा होने वाली थी, वार्ता में तेजी लाई गई थी।

मिड डे मील वर्करों की 12 दिन की हड़ताल

राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्करों के लंबित बिलों को जारी करने की घोषणा की है। इस अवसर पर एटक के राज्य मुख्यालय सत्यनारायणा रेड्डी भवन में एक मीटिंग की गई।

मीटिंग की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष प्रेम पवनी ने की। मीटिंग को डॉ. बी.वी. विजयलक्ष्मी और राज्य एटक महासचिव एस. बलराज ने भी संबोधित किया और सरकार को धन्यवाद किया। परंतु उन्होंने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि बिलों का भुगतान नहीं होता। इस समय सरकार उन्हें 3 हजार रु. मासिक का भुगतान करती है, परंतु यदि सुबह का

नाश्ता भी बनाया जाना है तो उन्हें 10 हजार रु. मासिक देना होगा। उन्होंने यह भी मांग कि सरकार बुनियादी जरूरी चीजों– अंडे, तेल, गैस, नमक, बर्तन आदि का प्रावधान करेगी।

मीटिंग में महासचिव ए. रवीन्द्र, कार्यकारी अध्यक्ष पी. रमेश, एस.पी. विजयलक्ष्मी, उपमहासचिव कुंतला दशरथ, उपाध्यक्ष– राममूर्ति, सैलू, मुमताज, वेंकटेश, सहसचिव– रामकृष्णा, पी. प्रोमिला, एस. रमा, जे. शोभा, लक्ष्मण, वसन्ता, मंगा, ललिता, ओ. रमेश आदि भी उपस्थित थे।

राजनीतिक अभियान चलाएगी भाकपा

पटना, 9 अक्टूबर, 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि पार्टी ने पूरे राज्य में सघन राजनीतिक अभियान चलाने का फैसला लिया है। बिहार में 16 से 31 अक्टूबर तक मोटर साईकिल रैली, आम सभा, जीबी बैठक, नुक्कड़ सभा, दीवाल लेखन आदि के माध्यम से केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का भंडा फोड किया जाएगा और दो नवम्बर को पटना में आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में भाग लेने की अपील की जाएगी। पटना में 26 अक्टूबर से लेकर एक नवम्बर तक जन सेवा दल का राज्यस्तरीय कैंप लगाया जाएगा।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से आम जनता परेशान है। विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण महगांई आसमान छू रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस सरकार में गरीबों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। इस सरकार में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसी के मद्देनजर भाकपा ने नारा दिया है भाजपा हटाओ, देश बचाओ और नया भारत बनाओ। इसी नारों को लेकर भाकपा जनता के बीच जाएगी और केन्द्र सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत कराएगी और अगली कड़ी में दो नवम्बर को पटना के गांधी मैदान में रैली होगी। रैली में पूरे राज्य से तीन लाख से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। भाकपा ने राज्य की जनता से राजनीतिक अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोनः 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.